राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात,संस्करण बुधवार,१२ मई २०२१ वर्ष-४, अंक -१०८ पृष्ठ-०८ मूल्य-०१रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित टास्क फोर्स ने आक्सीजन उत्पादन और सप्लाई को लेकर दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली। आक्सीजन के आवंटन मसले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित टास्क फोर्स का मानना है कि वर्तमान हालात और कोरोना संक्रमण की अप्रत्याशित स्थिति में आक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति के लिए जो कुछ किया गया, वह अभूतपूर्व है। समस्या ढांचागत है। उसे भी बहुत कुछ दुरुस्त किया गया है। जरूरत है आक्सीजन उपयोग के सही प्रबंधन की। पिछले एक पखवाड़े में ही जहां उत्पादन क्षमता में उछाल आया, वहीं अगर सप्लाई की बात हो तो उसमें दोगुना तक बढ़ोतरी हुई।

आक्सीजन आवंटन पर चर्चा के लिए रविवार को हुई थी पहली बैठक-पहली लहर के वक्त 14 सितंबर, 2020 को सबसे ज्यादा केस लोड था। तब भारत में 10.15 लाख एक्टिव केस थे और रोजाना लगभग एक लाख नए केस आ रहे थे। तब राज्यों को लगभग 3,000 मीट्रिक टन आक्सीजन दी गई थी। एक मार्च को इसकी जरूरत घटकर 1,318 मीट्रिक टन रह गई थी। लेकिन जरूरत के अनुसार नौ मई को राज्यों को लगभग 9,000 मीट्रिक टन आक्सीजन की सप्लाई की गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से शनिवार को गठित 12 सदस्यीय टास्क फोर्स की पहली बैठक रविवार को हुई तो सभी सदस्यों ने इसे सराहा। सूत्रों के अनुसार, सदस्यों का मानना था कि आक्सीजन के सही उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत है। तीन सदस्यों ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि उन्होंने 15-20 फीसद आक्सीजन की बर्बादी रोकी है। ध्यान रहे कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी बार-बार आगाह किया जा रहा है कि आक्सीजन को किस तरह बचाया जाए। कुछ सदस्यों ने आक्सीजन की कालाबाजारी पर चिंता जताई तो एक सदस्य ने केवल आशंका में भर्ती होने वाले मरीजों पर ध्यान देने की बात कही। सूत्रों की मानें तो आक्सीजन आवंटन की वर्तमान व्यवस्था में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं है।

तिरुपति के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में पांच मिनट की देरी

11 कोरोना मरीजों की गई जान

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कोरोना के 11 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। ऑक्सीजन की सप्लाई में सिर्फ पांच मिनट की देरी हुई थी, जिस दौरान वहां भर्ती 11 मरीजों की जान चली गई। वहीं, मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। चित्तूर के जिला कलेक्टर एम हरि नारायणन के मुताबिक, यह घटना तिरुपति के रुइया अस्पताल की है। इसे कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। उनके मुताबिक, सभी मरीज आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। अचानक ऑक्सीजन की कमी के चलते 11 मरीजों की जान चली गई। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन खत्म होने पर सिलेंडर दोबारा भरने में पांच मिनट का अंतराल था। सिलेंडर का दबाव कम होने के कारण मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉ. भारती का कहना है कि यहां कोविड के अलावा अन्य मरीज भी भर्ती होते हैं। कुछ और मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहां लगभग 700 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस घटना पर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले भी कई और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना मरीजों की जान जा चुकी है। हाल ही में दिल्ली के बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया था, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल थे। अस्पताल में एक मई को दोपहर 12 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसके बाद डेढ़ घंटे के बाद सप्लाई मिली। वहीं, कर्नाटक के हुबली में श्री भानजी डी खिमजी लाइफलाइन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पांच कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी।

- तिरुपति के रुइया अस्पताल में ऑक्सिजन की कमी से 11 की मौत
- जिला कलेक्टर ने बताया कि ऑक्सिजन लोड करने में 5 मिनट का समय लगा
- सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इस घटना की जांच के आदेश दिए

मोदी के मंत्री बोले-

कोरोना की दूसरी लहर भारत को इस कदर प्रभावित करेगी, WHO को भी नहीं था इसका अंदाजा

नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को बुरी तरह से प्रभावित किया है। रोज लाखों नए मामले सामने आ रहे हैं। हजारों मरीज की इस महामारी के कारण जान जा रही है। केंद्र सरकार पर लगातार इसे नजरअंदाज करने के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार कोरोना की दूसरी लहर का अंदाजा लगाने में पूरी तरह से विफल रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) सहित कोई भी यह अनुमान लगाने में सक्षम नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर भारत को इतना प्रभावित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत बहुत जल्द कोरोना की दूसरी लहर से बाहर निकल आएगा। रेड्डी ने सोमवार को तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरि जिले के बीबीनगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का दौरा किया, जहां उन्होंने कोरोना उपचार का जायजा लिया। मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार देश में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। लोगों के सहोग से भारत COVID की पहली लहर को पार पाने में सक्षम हुआ था। बहुत जल्द दूसरी लहर से भी हम बाहर निकल आएंगे। WHO सहित कोई भी यह अनुमान लगाने में सक्षम नहीं था कि COVID

की दूसरी लहर हमें बहुत प्रभावित करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि ऑक्सीजन और वैक्सीन के साथ COVID के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की मांग को पूरा करने के लिए विनिर्माण इकाइयां 24×7 चल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य देशों से अधिक ऑक्सीजन, टीके और दवाएं आयात की जा रही हैं। रेड्डी ने आगे कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बहुत सस्ती कीमत पर वैक्सीन लाने के लिए काम कर रहा है।

देश के सभी मेडिकल कॉलेज के सभी बेड होंगे ऑक्सीजन से लैस

6 महीने में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

नई दिल्ली। देश के सभी मेडिकल कॉलेज के सभी बेड होंगे ऑक्सीजन से लैस, 6 महीने में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश कोरोना महामारी के बीच देश में पैदा हुए ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए कई स्तरों पर काम चल रहा है। इसी सिलसिले में नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने देशभर के सभी मेडिकल कॉलेजों को छह महीने के भीतर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई करा रहे सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को यह प्लांट लगाना अनिवार्य होगा। भविष्य में कॉलेजों को संचालन की अनुमति के लिए भी संयंत्र को एक आवश्यक संसाधन माना जाएगा। एनएमसी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज पीएसए या वीएसए ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना करें। ये दोनों अलग-अलग तकनीक के संयंत्र हैं जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं। दूसरे, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को तरल ऑक्सीजन के भंडारण के लिए एक ऑक्सीजन टैंक की स्थापना भी करनी होगी। जिन अस्पतालों के पास अब तक यह टैंक

नहीं है, उन्हें तत्काल यह लगाना होगा। एनएमसी ने कहा कि उपरोक्त दो उपायों के अलावा सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन सभी बिस्तरों तक पाइप के जरिये ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिनमें गंभीर या ऑक्सीजन की जरूरत वाले रोगियों को भर्ती किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य आदेश में एनएमसी ने सभी मेडिकल कॉलेजों में 2022 तक आपातकालीन चिकित्सा विभाग की स्थापना करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि देशभर में 542 मेडिकल कॉलेज हैं, जो एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई कराते हैं।

ताकि चिकित्सकीय ढांचे का हो बेहतर इस्तेमाल-इस मुहिम के पीछे सरकार की कोशिश है कि कोरोना जैसी महामारी की स्थिति में मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकीय ढांचे का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सकेगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब उनका ढांचा मजबूत होगा। मौजूदा दौर में कई मेडिकल कॉलेजों के बिस्तरों का इसलिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। गिने-चुने ही मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास अपने ऑक्सीजन संयंत्र हैं। ये भी सरकारी में हैं। निजी कॉलेजों में यह सुविधा कहीं-कहीं ही है।

अंतिम वर्ष को छोड़ विश्वविद्यालयों के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। हालांकि अब तक जो स्थिति है, उसमें ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन को आधार बनाया है। यूजीसी के सचिव डॉ. रजनीश जैन के मुताबिक विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान होते हैं। ऐसे में उन्हें परीक्षाओं और शैक्षणिक सत्र आदि को लेकर अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने का पूरा अधिकार है। यूजीसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव देश के अलग-अलग हिस्सों में कम और ज्यादा है। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर इस बार कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन अभी नहीं बनाई गई है। इस बीच, विश्वविद्यालयों ने स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक आकलन या फिर पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करके प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई-अगस्त में कराने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। हालांकि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला जून के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा।

8 राज्यों के लिए दूत बना रेलवे, 121 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 4709 मीट्रिक टन 'जीवन रक्षक' भेजा

नई दिल्ली। रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब गति पकड़ती जा रही हैं। यह ट्रेन आठ राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति कर रही है। रेलवे ने अभी तक 121 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 295 टैंकरों में 4709 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा ने कहा है कि भारतीय रेल की प्राथमिकता इस समय देश में ऑक्सीजन आपूर्ति को जल्द से जल्द सुनिश्चित करना है। इसमें वह ऑक्सीजन आपूर्ति में आने वाली परिवहन लागत को भी नहीं देख रही है। चाहे उसे दो टैंकर ले जाने हो या वह उन टैंकरों को लेकर ऑक्सीजन प्लांट तक जा रही हैं और

वापस संबंधित राज्यों तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल से रेलवे ने अपनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया था और अभी तक 121 फेरों के जरिए 295 टैंकरों में 4709 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। इनमें से 100 टैंकर दिल्ली को पहुंचाए गए हैं। उत्तर प्रदेश को 98, मध्य प्रदेश को 27, महाराष्ट्र को 18, हरियाणा को 40, तेलंगाना को 9 और राजस्थान को तीन टैंकर पहुंचाए गए हैं।

50 टैंकरों में 744 टन ऑक्सीजन लेकर रास्ते में हैं कई ट्रेन

रेलवे की विभिन्न ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन इस समय 50 टैंकरों में 744 टन मेडिकल ऑक्सीजन लेकर रास्ते में हैं। इनमें 12 टैंकर दिल्ली को, 15 टैंकर उत्तर प्रदेश को, 10 टैंकर हरियाणा को, कर्नाटक को चार टैंकर, महाराष्ट्र को तीन तीन टैंकर ले जाए जा रहे हैं।

मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या में कमी आई

एक सवाल के जवाब में सुनीत शर्मा ने कहा है कि कोरोना की पाबंदियों के बाद अब रेलवे की मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या में भी कमी आई है। कोरोना काल के पहले 1768 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहे थे, जबकि इस समय इनकी संख्या 1182 विशेष मेल एक्सप्रेस है। उपनगरीय ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की संख्या में भी कमी की गई है। बहुत सी ट्रेन इसलिए बंद की गई है क्योंकि उनसे संक्रमण फैलने का खतरा था और दूसरी वजह यात्रियों की भारी कमी भी रही है। हालांकि राज्यों की मांग पर अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जा रही हैं।

कोवैक्सिन, कोविशील्ड या स्पूतनिक ? अब मनचाही वैक्सीन लगाने का मिलेगा विकल्प

नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब लोगों को मनचाही वैक्सीन लगाने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए कोविन पोर्टल पर बदलाव किए गए हैं। इसी कड़ी में अब कोविन पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने से पूर्व यह भी देखा जा सकेगा कि किस टीकाकरण केंद्र पर कौन सा टीका लग रहा है। साथ ही उम्र के हिसाब से टीकाकरण केंद्रों खोजने की सुविधा भी प्रदान की गई है। क्योंकि सभी केंद्रों में सभी उम्र के लोगों को टीके नहीं लगते हैं।

45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण से पूर्व पंजीकरण की सलाह दी जाती है। जबकि 18-44 आयु वर्ग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। कोविन पर पंजीकरण कराने के बाद टीकाकरण केंद्र के चयन की सुविधा दी गई है। इस दौरान पोर्टल पर यह भी प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस केंद्र पर कोविशील्ड लग रही है और कहां पर कोवैक्सीन। इससे लोगों को टीके का चयन करने की सुविधा मिलने लगी है। पहले सरकार ने कहा था कि लोगों को टीके के चयन की सुविधा नहीं दी जा सकती है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह बदलाव इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि जिन लोगों को दूसरी डोज लेनी है, उन्हें यह पता रहे कि किस केंद्र पर कौन सा टीका लग रहा है। दरअसल, कोवैक्सीन की आपूर्ति कम है तथा बहुत कम केंद्रों पर उसकी उपलब्धता है। दूसरे, एक-डेढ़ महीने पहले जिस केंद्र पर किसी व्यक्ति ने कोवैक्सीन लगाई है, यह जरूरी नहीं कि आगे भी उस केंद्र पर वही टीका उपलब्ध हो। फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी केंद्र पर टीका लगा सकता है। इसलिए

कोविन पर यह जानकारी दी जा रही है कि किस केंद्र पर कौन सा टीका लगाया जा रहा है। टीके को क्लिक करके केंद्र सर्च करने की सुविधा भी है। इससे दूसरी खुराक लेने वालों को भी सहूलियत होगी।

टीकाकरण केंद्र सर्च करने की सुविधा भी

इसी प्रकार आयु के हिसाब से भी टीकाकरण केंद्र सर्च करने की सुविधा भी दी गई है। 45 से अधिक आयु के लोगों को जिन केंद्रों पर टीका लग रहा है, उनमें जरूरी नहीं कि 45 से कम वालों को भी लगता हो। इसलिए उम्र के हिसाब से सर्च करने की सुविधा भी दी गई है। 45 से कम उम्र के लोगों के लिए ज्यादातर राज्यों ने अलग टीकाकरण केंद्र बनाये हैं। ऐसे में इन आयु वर्ग के लोगों को कोविन पर अपना टीकाकरकर केंद्र सर्च करने में सहूलियत होती है। इसी प्रकार पिनकोड और जिले के आधार पर भी टीकाकरण केंद्र खोजने की सुविधा पोर्टल पर दी गई है।

बिना अप्वाइंटमेंट के टीकाकरण

पोर्टल पर यह भी सुविधा दी गई है कि 45 साल से अधिक उम्र के लोग बिना किसी केंद्र के चयन के भी पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण पूरा करने के बाद उनका चार अंको का विशेष सुरक्षा कोड आ जाता है जिसे नोट कर या सेव कर वह किसी भी टीकाकरण केंद्र पर जा सकते हैं। और फोन नंबर और विशेष कोड बताकर वह टीका लगा सकते हैं। ऐसे में उनकी किसी एक टीकाकरण केंद्र पर इंतजार करने की बाध्यता नहीं रहेगी। बता दें कि हाल में कोविन पर चार अंकों का विशेष सुरक्षा कोड शुरू किया गया है। जब टीका लगाने वाला यह कोड़ बताता है और उसे पोर्टल में दर्ज किया जाता है तभी माना जाएगा कि टीकाकरण हो गया है। इसके बाद ही टीके का प्रमाण पत्र उत्पन्न होता है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

तर्कसंगत वैक्सीन नीति

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि कोविड के टीकाकरण के मामले में वह सरकार को नीतियां बनाने दे और कोई दखल न दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से ही इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा था कि पहली नजर में टीकाकरण की मौजूदा सरकारी नीति संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जन-स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत की नजर में सरकार की यह वह नीति है, जिसके मुताबिक, वैक्सीन निर्माता कुल वैक्सीन उत्पादन का आधा केंद्र सरकार को देंगे और आधा जो बचेगा, उसमें से आधा-आधा राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को दिया जाएगा। इस नीति में यह भी गौरतलब है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी अस्पताल, तीनों के लिए अलग-अलग कीमतें तय की गई हैं और तीनों में काफी फर्क है। केंद्र सरकार को जिस कीमत पर वैक्सीन मिलेगी, राज्य सरकार को उससे लगभग दोगुने दाम पर और निजी क्षेत्र को चौगुने दाम पर मिलेगी। इसी के साथ 18 से 44 की उम्र के लोगों को टीका लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को अपने कोटे से ही पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी भेदभाव को लेकर सवाल उठाया है। सरकार भले ही कह रही है कि उसने तमाम विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करके यह नीति बनाई है और सुप्रीम कोर्ट में दो सौ आठ पन्नों का हलफनामा भी दिया है, पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कई अन्य जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इस नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यह अब भी स्पष्ट नहीं होता है कि एक ही वैक्सीन की तीन कीमतें क्यों और किस आधार पर तय की गई हैं? अगर सीरम इंस्टीट्यूट कोविशिल्ड वैक्सीन अब तक 150 रुपये में बेच रहा था और आइंदा भी केंद्र को इसी दाम पर बेचेगा, तो राज्यों या निजी अस्पतालों से दोगुने, चौगुने दाम वसूलने का क्या तर्क है? सरकार का तर्क सैद्धांतिक रूप से सही है कि कार्यपालिका को अपना काम करने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन अगर मामला जन-स्वास्थ्य का हो और महामारी से लाखों लोग पीड़ित हों, तब प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण नीति पर सवाल खड़ा करना न्यायपालिका का भी कर्तव्य है।

इस नीति के साथ कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं और हो रहे हैं। जब वैक्सीन निर्माता किसी ग्राहक को वही वैक्सीन चार गुना दाम पर बेच सकते हैं, तो वे कम दाम देने वाले ग्राहक को क्यों बेचेंगे? केंद्र सरकार तो अपने रसूख का फायदा उठाकर अपना हिस्सा हासिल कर लेगी, पर राज्यों के हिस्से में तो गड़बड़ी करना संभव होगा, फिर राज्य सरकारों पर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। इसके नतीजे दिखने लगे हैं, अभी से राज्य सरकारों के पास वैक्सीन की कमी होने लगी है। निजी अस्पतालों को मिलने वाली सारी वैक्सीन भी बड़े कॉरपोरेट अस्पताल समूह जुटा ले रहे हैं, छोटे अस्पतालों तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं रही। बड़े अस्पताल वैक्सीन की कीमत और अपना खर्च ज्यादा दिखाकर मनमाने दाम वसूल रहे हैं। हमारे यहां वैक्सीन दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी बिक रही है। लोकतंत्र में यह जरूरी है कि सरकार के फैसले न्यायपूर्ण और पारदर्शी हों, उन फैसलों के तर्क को जनता के साथ साझा किया जाए। अब भी वक्त है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर एक ज्यादा सरल और तर्कसंगत वैक्सीन नीति बनाए। कोरोना से लड़ने के लिए यह बहुत जरूरी है ।

त्वरित तैयारी जमीन पर

उप्र के कई जिलों में 10 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। ऐसा देखने में आया कि कई वैक्सिनेशन केंद्रों पर अफरातफरी का माहौल था। दिल्ली में भी 1 मई से 18 से 44 साल के आयुवर्ग के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ, यहां भी शुरु आती दौर में काफी समस्याएं आइफा मूल समस्या वैक्सीन की उपलब्धता की है। 18 साल से ऊपर की आबादी की भारत में जनसंख्या करीब 94 करोड़ है। यह बहुत बड़ी आबादी है। इतनी जनसंख्या तक वैक्सीन पहुंचाना बहुत महद्मवाकांक्षी लक्ष्य है। भारत में अब तक करीब 17 करोड़ की आबादी ऐसी है, जिसे कम से एक कोरोना टीका मिल चुका है। 17 करोड़ आबादी का मतलब की 34 न्यूजीलैंड और 17 इजरायल जितनी आबादी को कम से एक टीका मिल चुका है भारत में। पर भारत के लिहाज से अभी कुल आबादी के बीस प्रतिशत हिस्से तक भी टीका ना पहुंच पाया है। यानी टीकाकरण की चुनौतियां भारत में विकट हैं। गौर की बात यह है कि 18 से 44 साल के आयुवर्ग को टीका बहुत जरूरी इसलिए है कि यह वर्ग अर्थव्यवस्था में बहुत महद्मवपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे अभी के जो हालात हैं, उनमें एक उम्मीद तो यह बंधती है कि खासकर उत्तर प्रदेश में कोरोना की यह लहर अपने शिखर पर पहुंच चुकी है यानी अब संक्रमितों की तादाद में उत्तरोत्तर कमी आएगी। पर मूल मसला यह भी है कि कोरोना के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तमाम स्तरों पर मार्च 2020 में यह घोषणा की जा रही थी कि कोरोना पर विजय हासिल कर ली है भारत में। फिर अप्रैल में कोरोना ने ऐसा प्रहार किया कि भारत में तमाम तैयारियां औंधे मुंह दिखायी दीं। कुल मिलाकर इस हकीकत से मुंह नहीं चुराया जा सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आगामी नवम्बर में दस्तक दे सकती है। तब के लिए हमारे पास क्या तैयारियां हैं। अस्पताल ऑक्सीजन, वेंटीलेटर की व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं पर हरेक को कम-से-कम एक टीका लग जाए, यह तो सुनिश्चित करना होगा। मूल मसला यह भी है सिर्फ खबरों से कोरोना नहीं भागेगा। तमाम टीके उपलब्ध होंग और आसानी से लगाए जा सकें, यह भी सुनिश्चित करना होगा। कुल मिलाकर लगता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर अभी बहुत होमवर्क बाकी है।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुरणिक

कुछ सिमल कथाएं

मान लीजिये कि एक पान मसाला है जिसका नाम है, सिमल और उसे बेचने वाले दो स्टारों के नाम हैं-विजय देवधन, फाहरुख खान।

कुछ सिमल कथाएं इस प्रकार हैं-कथा एक-सजल आंखों से सिमल-लाकडाऊन जबरदस्त था। पुलिस का फुलटू बंदोबस्त है। देश कोरोनाग्रस्त था। पर बंटी तलबग्रस्त था-सिमल पान मसाला, हाय सिमल पान मसाला खाना है। बंटी ने बाइक उठाई और निकल लिया आगे चौराहे पर पुलिस ने धर लिया बंटी को और पूछा-कौन सा खास काम करना है। बंटी ने विस्फारित नेत्रों के साथ कहा-सिमल पान मसाले के इंतजाम से भी ज्यादा महद्मवपूर्ण क्या है भला इस क्षणभंगुर दुनिया में। ड्यूटी पर तैनात थानेदार के नेत्र सजल हो उठे, हाय कितनी मर्मांतक पीड़ा-सिमल के इंतजाम से भी ज्यादा कौन सा काम महद्मवपूर्ण हो सकता है। थानेदार पिघल गए और बोले-सिमल का जुगाड़ हो जाए, तो लौटते में यहीं रुकना दोनों मिलकर सिमल का सेवन करेंगे। कथा नंबर दो- भईया बहुत अतजयां पड़ी हैं-पहले अकेले विजय देवधन बेचते थे सिमल पान मसाला। फिर फाहरुख खान ने निवेदन किया-हमसे भी बिकवा लो -तो सिमल पान मसाले के ठेले पर अब दो सेल्समैन हो लिये-विजय देवधन और फाहरु ख खान। एक दिन गन्नी देओल का फोन आया विजय देवधन के पास-भईया हमसे भी बिकवा लो सिमल पान मसाला। हमें भी बिठाओ सिमल के ठेले पर। विजय देवधन ने बताया-भाईजी भोत खराब टाइम चल्ला हैगा। बताओ जो फिल्म स्टार कार वगैरह बेचे करे थे, वो पान मसाला बेच रहे हैंगे। तुम काहे चक्कर में पड़ते हो, हैंडपंप बेचो, गर्मी का टाइम है। गन्नी देओल ने बताया-पब्लिक ऐसी हो गई है कि पानी-हैंडपंप से ज्यादा सिमल पान मसाले पर खर्च को तैयार है। हमसे भी बिकवा लो ना। विजय देवधन ने बताया-भईया बुरा ना मानना पचास फिल्म स्टारों की अतजयां पड़ी हैं, सब सिमल बेचने के चक्कर में हैं। क्या वक्त आ गया है कि बिक ही सिमल रहा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पान मसाले को पूरे सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए महंगी कारें बेचने वाले सुपर स्टार भी एक दिन पान मसाले के ठेले पर दिखते हैं-पान मसाला ले ले, पान मसाला ले लो।

बंगाल की हिंसा फासीवाद है

अवधेश कुमार

पश्चिम बंगाल में चुनाव उपरांत की राजनीतिक हिंसा ने पूरे देश को डराया है। लोगों की छोटी-बड़ी टोलियों, समूह द्वारा पुरुषों-महिलाओं की बेरहम पिटाई, उनको लहूलुहान किए जाने, घरों में तोड़फोड़, लूट, आगजनी, बमबारी आदि के दृश्य देखकर लगता ही नहीं कि कानून के किसी राज का अस्तित्व भी है। बंगाल की राजनीतिक हिंसा ने समय-समय पर पूरे देश को दहलाया है। कांग्रेस शासन काल के बाद के वर्षों से लेकर वाममोर्चा के पूरे शासनकाल में और ममता बनर्जी के अब तक के कार्यकाल में राजनीतिक हिंसा ने जो वीभत्स रूप दिखाया है सामान्यता लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

कोई सच्चाई से आंखें मूंद लें तो अलग बात है अन्यथा पूरी हिंसा का सीधा लक्ष्य उन लोगों को क्षति पहुंचाना दिख रहा है, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध मतदान किया या किसी स्तर पर दूसरी पातटयों का समर्थन किया। चूंकि भाजपा वहां दूसरी मुख्य पार्टी है इसलिए सबसे ज्यादा शिकार उसके नेता, कार्यकर्ता, सदस्य और समर्थक हो रहे हैं। माकपा और कांग्रेस ने भी यही आरोप लगाया है कि तृणमूल के लोग उनके कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। माकपा ने तो अपनी एक महिला नेत्री के हत्या की भी शिकायत की है। भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया। भले वैचारिक रूप से भाजपा और नरेंद्र मोदी के विरोधी या उनसे नफरत करने वाले अपना मुंह न खोलें, लेकिन सच सीधा दिख रहा है। स्थिति इतनी भयावह है कि अनेक क्षेत्रों से भाजपा के समर्थक अपना घर द्वार छोड़कर भाग रहे हैं। ये जान और इज्जत बचाने के लिए या तो बंगाल में ही कहीं छिपे हुए हैं या असमग बिहार, झारखंड आदि राज्यों में भागे हैं।

ये दृश्य वैसे ही हैं जैसे 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान और उसके बाद देखे गए थे। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने ममता सरकार के विरुद्ध तीखी टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करती हूं कि कोई हिंसा न करेंग हमारी ओर से नहीं होगा। साथ ही उन्होंने लोगों से भी कहा कि वो हिंसा न करें। अगर अब कोई हिंसा करेगा तो उसके विरुद्ध मैं कार्रवाई करूंगी। हिंसा की भयावहता, विकरालता और वीभत्सता को देखते हुए मुख्यमंत्री का यह बयान निराश और कई मायनों में गुस्सा भी पैदा करता है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब राज्यपाल ने अपने बयान में मुख्यमंत्री से संविधान और कानून का पालन करने तथा हिंसा रोकने की अपेक्षा का बयान दिया था तो ममता ने कहा कि अभी तक चुनाव आयोग के हाथ में व्यवस्था थी। इसके लिए जिम्मेवार चुनाव आयोग है। यह परेशान करने वाला है कि अभी तक उनकी ओर से कानून के तहत कठोर कार्रवाई करने का एक भी बयान नहीं दिया। हिंसा होती रहे, कानूनी एजेंसियां मूकदर्शक बनी रहें, सत्तारूढ़ पार्टी का कोई विधायक, सांसद, नेता इसकी निंदा और विरोध तक न करें तो प्रकारांतर से यही माना जाएगा कि हिंसा राज्य पोषित, राज्य प्रेरित और राज्य प्रायोजित है।

कई क्षेत्रों में हिंसा का रूप सांप्रदायिक हो जाना और भी भयावह है। एक समुदाय के लोग जहां भी अच्छी संख्या में हैं; उन्होंने दूसरे समुदाय की कम संख्या वाले लोगों पर जिस ढंग से हमला किया, महिलाओं तक को नहीं बख्शाग उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया उससे तो भाजपा के इस आरोप की पुष्टि होती है कि ममता ने अपने शासनकाल में उस अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है। यानी उनकी सांप्रदायिक सोच को मान्यता देना, गलत सही कामों पर आंख मूंदनाग कानूनी कार्रवाई से हरसंभव बचाना और कुल मिलाकर उनका मनोबल बढ़ाना। कायदे से तृणमूल के विधायकों, लोक सभा सांसदों, नेताओं सबको हिंसा के विरुद्ध कम से कम सड़कों पर आकर शांति की अपील करनी चाहिए थी या हिंसा करने वालों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया इसका मतलब साफ है कि ये भी उन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं, जिन्होंने मतदान में इनका साथ नहीं दिया या विरोध किया। वाममोर्चा से लेकर तृणमूल कांग्रेस ने इसी तरह की हिंसा को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए प्रश्रय दिया है। चुनाव के पूर्व ऐसे भय का वातावरण बनाओ कि कोई विरोध में मतदान करने न जाएग जाए तो हमारे पक्ष में मतदान करे, अगर विरोध में मतदान कर दिया तो चुनाव के उपरांत उसको सबक सिखाया जाए ताकि भविष्य में दूसरे लोग ऐसा करने का साहस न कर सके।

यही बंगाल में हो रहा है। हिंसा करने वाले की मानसिकता यही है कि जिन्होंने विरोधी पातटयों को मत दिया वे अपने कर्तव्यों से च्युत हुए हैं यानी उनको केवल तृणमूल के उम्मीदवारों को ही वोट देना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए उनको सजा देना हमारा अधिकार है। फासीवाद का इससे अलग कोई स्वरूप नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। जो लोग नरेंद्र मोदी या भाजपा का विरोध करते हैं वे करें लेकिन इस तरह की हिंसा सभी राजनीतिक विचारधाराओं की शत्रु है। सभी को राजनीतिक मतभेद भुलाकर एकजुट होकर ऐसे हिंसा के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जो लोग केंद्र सरकार द्वारा संविधान के तहत कार्रवाई, केंद्रीय सैन्य पुलिस बल भेजने, राष्ट्रपति शासन लागू करने आदि की मांग कर रहे हैं वे संविधान की व्यवस्था से अनिभज्ञ हैं।

राज्यों की कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की केंद्र के संवैधानिक अधिकार अत्यंत सीमित हैं। राष्ट्रपति शासन यानी आपातकाल को संविधान ने अंतिम विकल्प के रूप में अपनाने का सुझाव दिया है। वास्तव में यह राजनीतिक संघर्ष का विषय है। न्यायालय में जाना उचित है लेकिन फासीवादी हिंसा का हर स्तर पर अहिंसक तरीके से प्रतिरोध करना, उससे जूझना ही रास्ता है। दुर्भाग्य यह कि नेताओंग बुद्धिजीवियोंग पत्रकारों, एक्टिविस्टों आदि का एक बड़ा समूह भाजपा और नरेन्द्र मोदी के विरोध में मानसिक रूप से इस सीमा तक जा चुका है कि उसके विरुद्ध हिंसा, गैरकानूनी और असंवैधानिक कार्रवाइयों पर भी चुप्पी साध लेते हैं या भाजपा का ही दोष निकालते हैं। साफ है कि एकजुट लड़ाई संभव नहीं होगी, लेकिन जो लोग भी सहअस्तित्वकारी लोकतंत्र बनाए रखना की कल्पना करते हैं उनको अपना दायित्व समझ कर इसके विरुद्ध कमर कसनी होगी।

> दुर्भाग्य यह कि नेताओं, बुद्धिजीवियों, एक्टिविस्टों आदि का एक बड़ा समूह भाजपा और नरेन्द्र मोदी के विरोध में मानसिक रूप से इस सीमा तक जा चुका है कि उसके विरूद्ध हिंसा, गैरकानूनी और असंवैधानिक कार्रवाइयों पर भी चुप्पी साथ लेते हैं या भाजपा का ही दोष निकालते हैं। साफ है कि एकजुट लड़ाई संभव नहीं होगी, लेकिन जो लोग भी सहस्तित्वकारी लोकतंत्र बनाए रखना की कल्पना करते हैं उनकों अपना दायित्व समझ कर इसके विरूद्ध कमर कसनी होगी।

ऑक्सीजन उपयोग का ऑडिट

राज्यों व निजी अस्पतालों की जवाबदेही तय हो

अनूप भटनागर

प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार का प्रमुख हिस्सा है। कोरोना काल में इसके लिये देश में जमकर राजनीति हो रही है। कार्यपालिका ने इसमें न्यायपालिका को भी घसीट लिया है। आज न्यायपालिका फैसला कर रही है कि दिल्ली हो या कर्नाटक उसे कितने मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की रोजाना आवश्यकता है और फिर वह केन्द्र को उतनी ही मात्रा में आक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दे रही है। कर्नाटक को 1200 मीट्रिक टन से ज्यादा आक्सीजन मिल गयी है। दिल्ली को 700 टन मिली, लेकिन अब उसकी मांग 976 मीट्रिक टन पहुंच रही है। गुजरात भी 1600 मीट्रिक टन चाहता है।

इस बीच, ऑक्सीजन के आवंटन के मसले की पेचीदगी को देखते हुए शीर्ष अदालत ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और समानता के आधार पर चिकित्सकीय ऑक्सीजन के आवेदन की आवश्यकता महसूस करते हुए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। कार्यबल में विभिन्न प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों को शामिल किया गया है। यह कार्यबल देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर ऑक्सीजन की उपलब्धता और वितरण की स्थिति का आकलन करके अपनी सिफारिश देगा। कार्यबल राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और समता के आधार पर ऑक्सीजन के आवंटन का तरीका खोजेगा। यही नहीं, कार्यबल का लक्ष्य प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन की आपूर्ति के उपयोग के संबंध में ऑडिट करके जवाबदेही के बारे में सिफारिश करना है।

विडंबना है कि किसी भी मंच पर राज्यों से यह सवाल नहीं किया जा रहा कि आखिर कोरोना संक्रमण के पहले दौर के बाद उन्होंने अपने यहां स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और ऑक्सीजन आपूर्ति के लिये क्या कदम उठाये? क्या उन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिये अनुमानित आवश्यकता के अनुसार टैंकरों की व्यवस्था की थी? यह सही है कि ऑक्सीजन संकट पैदा होते ही केन्द्र सरकार और कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये कमर कसी। विदेशों से क्रॉयोजेनिक टैंकरों को वायुसेना के विमानों से मंगाया गया लेकिन इस संकटकाल में राज्यों ने क्या किया?

एक सवाल और है कि क्या ऑक्सीजन संकट और बिस्तरों तथा दवाओं की कमी के मामले में राज्य सरकारें और निजी अस्पताल अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं। राज्यों और निजी अस्पतालों, जो मरीजों से मोटी रकम लेते हैं, से सवाल किया जाना जरूरी है कि आखिर उन्होंने अपने यहां ऑक्सीजन संयंत्र अभी तक क्यों नहीं लगाये। यह पता लगाना भी जरूरी है कि आखिर देश के कितने अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन संयंत्र हैं। राज्यों ने निजी क्षेत्र के अस्पतालों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित की लेकिन उन्हें अपने यहां ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिये बाध्य नहीं किया। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अस्पतालों मे भी ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थिति कमोबेश ऐसी ही रही और अब पीएम केयर्स फण्ड से एम्स सहित कई अस्पतालों में करीब 550 ऑक्सीजन संयंत्र डीआरडीओ की मदद से लगाये जा रहे हैं।

हां, पिछले सप्ताह बंबई उच्च न्यायालय ने जरूर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से जानना चाहा कि अगर सांगली जैसे शहर में एक अस्पताल अपने यहां ऑक्सीजन संयंत्र लगा सकता है तो प्रदेश के अन्य अस्पताल ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से यह संयंत्र लगाने पर आने वाले खर्च के बारे में जानकारी मांगी है जो निश्चित ही ऑक्सीजन संकट से उबरने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है और दूसरे राज्यों को भी इससे सीख लेने की आवश्यकता है।

कोरोना महामारी की दूसरी भयावह लहर आने से पहले देश में ऑक्सीजन का इतना बड़ा संकट कभी पैदा नहीं हुआ था। इस संकट को देखने के बाद ही जनता को पता चला कि सरकारी अस्पतालों से लेकर बड़े-बड़े निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र हैं ही नहीं और जीवनदायिनी प्राणवायु की आवश्यकता पड़ने पर अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जीवन डोर निजी ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं की आपूर्ति पर टिकी हुई है।

एक ओर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं और घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर के सहारे जीवित व्यक्तियों के परिजन उन्हें भरवाने के लिये दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ऑक्सीजन के सिलेंडर की जमाखोरी भी हो रही है।

केन्द्र सरकार की सक्रियता और विदेशी सहायता के बाद देश में ऑक्सीजन की स्थिति में सुधार हो रहा है। केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय को भी बताया है कि इस समय उसका उत्पादन नौ हजार मीट्रिक टन से ज्यादा है जबकि इसकी मांग करीब छह हजार मीट्रिक टन है। मतलब मांग के मुकाबले गैस की उपलब्धता पर्याप्त है। दिक्कत सिर्फ उसकी ढुलाई में आ रही है। ऑक्सीजन के उपयोग के ऑडिट का सवाल जब पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत में उठा तो सबसे पहले दिल्ली सरकार ने इस विचार का विरोध किया था। इस विरोध की वजह समझ से परे थी।

उम्मीद की जानी चाहिए कि न्यायपालिका देश में चिकित्सकीय ऑक्सीजन के संकट से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये अस्पतालों को अपने यहां ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का न्यायिक आदेश देगी। देश में उपलब्ध ऑक्सीजन का राज्यों को आवंटन और इसके उपयोग का ऑडिट कराने का न्यायालय का प्रयास निश्चित ही सराहनीय है क्योंकि इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि क्या वास्तव में देश में ऑक्सीजन का संकट हो गया था या कुछ राज्यों ने जानबूझकर इस संकट को पैदा किया था।

मुद्दा

देशव्यापी लॉकडाउन क्योम नहीं?

रवि शंकर

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना संक्रमण के लाखों मामले सामने आ रहे हैं। हजारों मौतें हो रही हैं। ऐसे में देश में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की मांग पर बहस छिड़ गई है। यह ठीक है अप्रैल माह में कोरोना संक्रमण के बेलगाम होने के बाद कई राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन लगाया है, लेकिन केंद्र सरकार इस बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाने से बच रही है। इस बार यह जिम्मा केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ दिया है। इसकी कुछ राजनीतिक वजहें हो सकती हैंग लेकिन मुख्य वजहें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं।

सबसे बड़ी चिंता इकोनॉमी को लेकर है। गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था तो इसका अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था। इस भयावह अनुभव को देखते हुए ही शायद केंद्र सरकार एक बार फिर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने से बच रही हैं। भारत में 10 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों में या तो क्षेत्रीय लॉकडाउन लागू हैं या फिर रात का कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलें को देखते हुए देश के कई वैज्ञानिकग डॉक्टर, एक्सपर्ट यहाँ तक कि सरकार की खुद की कोरोना टास्कोर्स ने भी देश में 15 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को कह रहे हैं तो फिर सरकार ऐसा कर क्यों नहीं रही है? यहां तक कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसकी वकालत करते हुए कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका एक पूर्ण लॉकडाउन है। भारत की शीर्ष अदालत ने भी मोदी सरकार को दूसरी लहर की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह दी थी। अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट और व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉ. एंथोनी फॉसी ने भी भारत में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। एक इंटरव्यू में डॉ. फॉसी ने कहा कि कोरोना के संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए कुछ हफ्तों के लिए सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। इससे कोरोना के प्रसार पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। खैर,

भारत सरकार पर सबसे बड़ा दबाव उन लाखों डॉक्टरों और फ्रंटलाइन स्टाफ का है जो देश के हजारों अस्पतालों में दिन-रात काम कर रहे हैं लेकिन अपनी आँखों के सामने ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों को दम तोड़ते देख रहे हैं। अस्पतालों में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और दूसरे स्वास्थ्य यंत्रों की सख्त कमी को देखते हुए वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार कुछ हफ्तों के लिए देशभर में लॉकडाउन लगाए ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके और उन्हें कुछ राहत मिले। एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि देश में पिछले साल की तरह इस बार भी पूर्ण लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। यह सत्य है कि पिछले साल देश भर में अचानक से लगाए गए लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो गई थी। एक तिमाही में विकास दर -23.19 प्रतिशत पहुंच गई थी, ऐसी भयंकर गिरावट भारत की अर्थव्यवस्था में पहले कभी नहीं देखी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा था। शायद इसी कारण वो एक और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पक्ष में नजर नहीं आते हैं। लेकिन सरी तरं देश भर में डॉक्टरों और अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की बुरी हालत देखकर केंद्र सरकार को ये भी चिंता है कि कहीं डॉक्टर और नर्स मानिसक और शारीरिक रूप से जवाब न दे दें, उनका मनोबल कहीं जवाब न दे दे।

सरकारी हलकों में ये एक बड़ी चिंता का विषय है। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में दूसरी लहर का कहर ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि कोरोना वायरस का नया वैरियंट ज्यादा खतरनाक है। फिर भी बीते महीने यानी 20 अप्रैल को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में लागू करने के लिए कहा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार को एक बार फिर पूरे देश में तालाबंदी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार पिछले साल की तरह इस बार पूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने से क्यों कतरा रही हैग यह समझ से परे है। फिलहाल देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमीग्बेड की किल्लत और जरूरी दवाओं के अभाव में बीते कई दिनों से कई मरीजों की जान चली गई है। सरकारी आंकड़े भले ही मौत कम बताएं, लेकिन मोक्षधाम में भी अंतिम संस्कार के लिए लाइन लग रही है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि लॉकडाउन समय की मांग है।

वित्त मंत्रालय, NDB सामाजिक अवसंरचना वित्त पोषण, डिजिटल प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी आयोजित करेंगे

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) मिलकर सामाजिक अवसंरचना वित्त पोषण और डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के महत्व पर एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। भारतीय ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2021के तहत आर्थिक एवं वित्तीय साझेदारी एजेंडा के तहत इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसे इस साल के अंत में होने वाले 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस आभासी संगोष्ठी का आयोजन 13 मई 2021 को किया जाएगा। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद एनडीबी के अध्यक्ष माजकोस ट्रायजो का संबोधन होगा। बयान के मुताबिक कोविड-19 महामारी ने सामाजिक अवसंरचना में निवेश करने के महत्व पर फिर से बल दिया है और उन्नत तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित किया है। इस संगोष्ठी में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के प्रतिभागी शामिल होंगे।

इंडियाबुल्स एमएफ का 175 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करेगी ग्रोव

मुंबई: ऑनलाइन निवेश मंच ग्रोव ने मंगलवार को कहा कि वह इंडियाबुल्स म्यूचुअल फंड का 175 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ग्रोव इंडियाबुल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी (आईबीएएमसी) और ट्रस्टी कंपनी का कुल 175 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए की राशि नकद या समकक्ष घटकों के रूप में है। बयान के मुताबिक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस (पीएमएस) कारोबार को आईबीएएमसी के मौजूदा ढांचे से अलग कर दिया जाएगा और ये इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अधीन रहेंगे। बाजार नियामक सेबी ने फिनटेक कंपनियों जैसे डिजिटल मंचों को म्यूचुअल फंड कारोबार में प्रवेश करने की इजाजात दी थी और इसके बाद ग्रोव परिसंपत्ति प्रबंधन कारोबार में प्रवेश करने वाली पहली फिनटेक कंपनी बन गई है।

कोविड संकट: ऑक्सीजन की कमी होगी दूर, HUL भारत में 4,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देगी

नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच एफएमसीजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) ने मंगलवार को कहा कि वह भारत को 4,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देगी, जिससे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। एचयूएल ने एक बयान में कहा कि कंपनी सबसे अधिक प्रभावित शहरों में 4,000 कंसंट्रेटर भेजेगी, जिसमें दिल्ली, लखनऊ और बैंगलोर शामिल हैं। बयान के मुताबिक, एचयूएल इसके लिए केवीएन फाउंडेशन और पोर्टिया के साथ साझेदारी कर रहा है, जो भारत की सबसे बड़ी होम हेल्थकेयर कंपनी है, जिसके तहत जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जाएंगे। बयान के मुताबिक पोर्टिया के जरिए 3,000 कंसंट्रेटर रोगियों को निशुल्क दिए जाएंगे, शेष कंसंट्रेटर को एचयूएल द्वारा 20 शहरों के अस्पतालों को दान किया जाएगा।

बायोकॉन प्रमुख ने कोविड-19 वैक्सीन की कमी पर जताई चिंता

बिजनेस डेस्क:

बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार-शॉ ने कोविड-19 की वैक्सीन की कमी पर चिंता जताते हुए उनकी उपलब्धता के बारे में सरकार से पारदर्शिता की मांग की है, ताकि आम लोग धैर्य से काम लें और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। भारत सरकार ने एक मई से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए खोलने की घोषणा की है। मजूमदार-शॉ ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय को टैग करके एक ट्वीट किया, ÷इस बात को लेकर बेहद चिंतित हूं कि वैक्सीन की आपूर्ति इतनी कम क्यों हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय, क्या हम यह जान सकते हैं कि हर महीने सात करोड़ खुराक कहां जा रही है? यदि आपूर्ति की समय सारिणी सार्वजनिक की जाए, तो लोग धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में मीडिया में खबरें आई थीं कि केंद्र ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड वैक्सीन की 11 करोड़ खुराकों के लिए शत प्रतिशत अग्रिम के तौर पर 1,732.50 करोड़ रुपए 28 अप्रैल को दे दिए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड को कोवैक्सीन की 5 करोड़ खुराकों के लिए 28 अप्रैल को 787.50 करोड़ रुपए जारी किए गए।

5जी तकनीक से फैल रहा कोरोना वायरस का जानिए पूरा सच, DoT ने किया क्लेरिफाई

बिजनेस डेस्क: सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार एक बार फिर गर्म है और इस बार 5जी तकनीक अफवाह फैलाने वालों के निशाने पर है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कई भ्रामक संदेश फैलाए जा रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि 5जी मोबाइल टॉवरों की टेस्टिंग से कोरोना वायरस की दूसरी लहर पैदा हुई है। अफवाहों के चलते दूरसंचार टावरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने एक प्रेस बयान में कहा है कि ये संदेश गलत हैं। बयान में कहा है कि आम जनता को सूचित किया जाता है कि 5जी तकनीक और कोविड-19 के फैलने में कोई संबंध नहीं है और उनसे अपील की जाती है कि वे इस मामले में गलत सूचनाओं और अफवाहों से भ्रमित न हों। आगे कहा गया है की 5जी तकनीक को कोविड-19 महामारी से जोड़ने के दावे झूठे हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 5जी नेटवर्क की टेस्टिंग अभी भारत में कहीं भी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में यह दावे कि भारत में 5जी ट्रायल्स या नेटवर्क कोरोना वायरस पैदा कर रहे हैं, निराधार और गलत हैं। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मोबाइल टावरों से नॉन-आयोनाइजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती हैं, जो कि बहुत कमजोर होती हैं और मनुष्यों समेत किसी भी जीवित कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। दूरसंचार विभाग ने रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड की एक्सपोजर लिमिट के लिए मानक निर्धारित किए हैं, जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन-आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन (आईसीएनआईआरपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से तय की गई सुरक्षित सीमा से करीब 10 गुना अधिक कठोर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी साफ किया है की वायरस रेडियो तरंगों/मोबाइल नेटवर्क से नहीं फैल सकता है।

ओयो अपने ऐप पर भागीदार होटलों के कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति बताएगा

नई दिल्ली: होटल इंडस्ट्री की कंपनी ओयो ने मंगलवार को कहा कि वह अपने ऐप पर भागीदार होटलों के कर्मचारियों के कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति को बताएगा, क्योंकि उसका मानना है कि ऐसी पहल से ग्राहकों के बीच भरोसा और बढ़ेगा। ओयो ने कहा कि पर्यटन और यात्रा उद्योग को पटरी पर लाने के लिए टीकाकरण बेहद महत्वपूर्ण है। ओयो के संस्थापक और समूह सीईओ रितेश अग्रवाल ने एक ट्वीट में कहा, कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण पहल है। ओयो में हम होटल कर्मचारियों की टीकाकरण की स्थिति को दर्शाने के लिए एक नया फीचर वैक्सीनएड पेश कर रहे हैं। ओयो के सर्वेक्षणों से पता चला है कि 87 प्रतिशत लोग जब फिर से यात्रा की योजना बनाएंगे, तो वे प्रतिरक्षित कर्मचारियों वाले होटल को पसंद करेंगे।

कमजोर वैश्विक रुख के साथ सेंसेक्स 341 अंक लुढ़का, निफ्टी 14,900 के नीचे बंद

बिजनेस डेस्क:

शेयर बाजार में पिछले चार कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर मंगलवार को विराम लग गया और सेंसेक्स 341 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, कोटक बैंक और टीसीएस जैसी सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों के शेयरों में गिरावट से बाजार नीचे आया। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 340.60 अंक यानी 0.69 प्रतिशत घटकर 49,161.81 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 91.60 अंक यानी 0.61 प्रतिशत की गिरावट के साथ 14,850.75 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक 3 प्रतिशत का नुकसान कोटक बैंक को हुआ। इसके अलावा एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, एचयूएल और टाइटन आदि शेयरों में गिरावट रही। दूसरी तरफ, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावरग्रिड, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट और एसबीआई लाभ में रहने वाले शेयरों में शामिल हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी के अनुसार वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख और बिकवाली दबाव से मानक सूचकांक नीचे आए। उन्होंने कहा, ''विभिन्न देशों में जिंसों के दाम तेजी से बढ़ने के बाद महंगाई बढ़ने को लेकर चिंता के बीच एशियाई बाजारों में गिरावट रही। इसके अलावा चीन में मुद्रास्फीति आंकड़ा भी धारणा को प्रभावित कर रहा है।

एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग, टोक्यो और सोल में गिरावट रही जबकि शंघाई बाजार लाभ में रहा। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरूआती कारोबार में गिरावट का रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67.87 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

क्रिसिल ने भी घटाया भारत की वृद्धि दर का अनुमान, 8.2% पर किया सीमित

बिजनेस डेस्क:

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमान को घटाकर सोमवार को 8.2 प्रतिशत कर दिया जबकि पहले उसने 11 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान रखा था। एजेंसी ने कहा कि यदि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जून अंत तक के बाद कम हो जाए तो वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि 8.2 प्रतिशत रह सकती है। उसने स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत की अनुमानित 11 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर के घटने का जोखिम हो सकता है।

तो और घट सकती है आर्थिक वृद्धि

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर यदि मई अंत तक रहती है तो आर्थिक वृद्धि 9.8 प्रतिशत रह सकती है। अगर लहर जुलाई तक रही तो वृद्धि दर के 8.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

आधिकारिक अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत संकुचित हुई थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप के बाद वृद्धि दर के घटने का जोखिम बन गया है।

15% राजस्व वृद्धि का अनुमान

एजेंसी ने कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण का प्रसार और टीकाकरण है। महामारी की दूसरी लहर वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े पर फैली लेकिन भारत में संक्रमण दर के बढ़ने के साथ मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। उसने कहा कि भारत पूरी तरह से टीकाकरण करने वाली आबादी के मामले में काफी नीचे है। यदि अक्टूबर तक देश की आधी आबादी को कोरोना का टीका लग जाता है तो यह अच्छा होगा। रेटिंग एजेंसी ने हालांकि 15 प्रतिशत राजस्व वृद्धि का अनुमान बनाए रखा है।

एचएफसीएल का चौथी तिमाही मुनाफा कई गुणा बढ़कर 86 करोड़ रुपये हुआ

नयी दिल्ली. दूरसंचार गीयर बनाने वाली घरेलू कंपनी एचएफसीएल ने सोमवार को कहा कि मार्च में समाप्त चौथी तिमाही के दौरान उसका एकीकृत शुद्ध लाभ कई गुणा बढ़कर 86.47 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने इससे पिछले साल इसी तिमाही में 8.7 करोड रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। कंनी ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कारोबारी गतिविधियां ऊंची रही हैं। पिछले साल की आखिरी तिमाही में महामारी के कारण कारोबार कमजोर रहा। एचएफसीएल के प्रबंध निदेशक महेन्द्र नाहटा ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''परियोजनाओं के कार्य बेहतर ढंग से पूरा होने और आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की ऊंची मांग से वृद्धि को समर्थन मिला है।'' उन्होंने कहा कि सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, भारतनेट से होने वाला कारोबार, 5जी की शुरुआत, आप्टिकल फाइबर और ओएफसी की मांग से आने वाले समय में कारोबार की दिशा तय होगी। नाहटा ने कहा, ''अगले पांच साल भारत में दूरसंचार कंपनियों के लिये अच्छे कारोबारी अवसर लेकर आयेंगे। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा अच्छी है और हम भी इस योजना का लाभ उठाने के बारे में देख रहे हैं।'' आलोच्य तिमाही के दौरान एचएफसीएल का एकीकृत राजस्व दोगुनु से अधिक होकर 1,391.4 करोड़ रुपये हो गया।

अब घर बैठे वीडियो से करा सकेंगे KYC, RBI ने आसान किए नियम

मुंबई:

रिजर्व बैंक ने सोमवार को अपने ग्राहक को पहचानिए (केवाईसी) के संदर्भ में जारी मास्टर निर्देशों में संशोधन किया। यह संशोधन ग्राहकों की वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) का अधिक लाभ उठाने तथा केवाईसी को समय-समय पर अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया। वी-सीआईपी बैंक ग्राहक की पहचान करने का एक वैकल्पिक तरीका है जिसमें ग्राहक के चेहरे को देखकर पहचान की जाती है। इसके तहत रिजर्व बैंक नियमन के तहत आने वाली इकाई का प्राधिकृत अधिकारी ग्राहक की जांच-परख करता है। इसके तहत ग्राहक के साथ श्रव्य-दृश्य बातचीत के आधार पर बिना किसी अड़चन के, सुरक्षित, जीवंत और सहमति के बाद पहचान के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसके नियमन के तहत आने वाली कंपनी व्यक्तिगत नए ग्राहक, प्रापरेएटरशिप फर्म के मामले में उसके मालिक, कानूनी इकाई के मामले में उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और लाभार्थी मालिक ग्राहक की जांच परख के लिए वी-सीआईपी प्रक्रिया को अपना सकते हैं। रिजर्व बैंक नियमन वाली इकाइयों में बैंक, एनबीएफसी और भुगतान प्रणाली परिचालक शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि ये इकाइयां बिना चेहरे के खोले गए खातों को चेहरे वाले में बदलने के लिए भी वी-सीआईपी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए वह आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी सत्यापन और पात्र ग्राहकों के लिए केवाईसी का सावधिक अद्यतन करने के लिए कर सकते हैं।

जल्द सस्ता होगा खाने का तेल, जानिए सरकार की क्या है योजना

बिजनेस डेस्क:

केंद्र सरकार ने सोमवार को उम्मीद जताई कि बंदरगाह पर मंजूरी मिलने के इंतजार में फंसे आयातित स्टॉक के जारी होने के बाद खाद्य तेलों की खुदरा कीमतें नरम पड़ जाएंगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में एक साल में 55.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके कारण पहले से ही कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट का सामना कर रहे उपभोक्ता की परेशानी और बढ़ी है। खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि सरकार कीमतों पर करीबी से नजर रखे हुए है। सचिव ने कहा कि तेल उद्योग ने हाल ही में इसका जिक्र किया है कि कोविड स्थिति के मद्देनजर सामान्य जोखिम विश्लेषण के रूप में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे परीक्षणों से संबंधित मंजूरी में देरी के कारण कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों पर कुछ स्टॉक फंसा है।

पिछले साल मई में 90 रुपए था भाव

उन्होंने एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस समस्या का सीमा शुल्क और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के साथ मिलकर समाधान किया गया है और जैसे ही यह स्टॉक को बाजार में जारी होगा, हमें खाद्य तेलों के दाम पर इसका असर होने की उम्मीद है। सचिव ने कहा कि खाद्य तेल की कमी को पूरा करने के लिए देश आयात पर निर्भर है। सालाना, देश में 75,000 करोड़ रुपए के खाद्य तेलों का आयात होता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल आठ मई को वनस्पति की खुदरा कीमत 55.55 प्रतिशत बढ़कर 140 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 90 रुपए प्रति किलोग्राम थी।

पाम ऑयल में 52त्न की तेजी

इसी तरह पाम ऑयल का खुदरा मूल्य 51.54 प्रतिशत बढ़कर 132.6 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, जो पहले 87.5 रुपए प्रति किलोग्राम था, सोया तेल का 50 प्रतिशत बढ़कर 158 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया जो पहले 105 रुपए प्रति किलोग्राम था, जबकि सरसों का तेल 49 प्रतिशत बढ़कर 163.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया जो पहले 110 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। उक्त अवधि में सोयाबीन तेल की खुदरा कीमत भी 37 प्रतिशत बढ़कर 132.6 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है जो पहले 87.5 रुपए किलो थी, जबकि मूंगफली तेल 38 प्रतिशत बढ़कर 180 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया जो पहले 130 रुपए प्रति किलोग्राम पर था।

साइबर एजेंसी ने किया अलर्ट, Vaccination के नाम पर आ रहे फेक SMS

बिजनेस डेस्क:

देश में कोरोना वायरस का संक्रमण और मौतों का सिलसिला जारी है। देश में दवाइयां, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर और वेंटिलेटर की कमी है। इस बीच लोगों की जरूरत का फायदा उठाने के लिए ठगी करने वाले सक्रिय हो गए हैं। दरअसल, कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने के साथ ही फर्जी टीका पंजीकरण एसएमएस भेजकर यूजर्स के एंड्रॉयड फोन में सेंध लगाई जा रही है और यूजर्स के डेटा तक पहुंच बनाई जा रही है। संघीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने आगाह किया है कि टीका तो जरूर लगवाएं लेकिन इसके लिए पंजीकरण सरकारी पोर्टल कोविन पर ही कराएं। टीकाकरण के लिए अंजान स्त्रोत से आए संदेशों पर दिए लिंक का इस्तेमाल न करें।

एजेंसी ने किया आगाह

एजेंसी ने आगाह किया है कि फर्जी पंजीकरण के नाम पर 5 तरह के नुकसानदेह एसएमएस आ रहे हैं। इनसे बचा जाना चाहिए। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी) आम लोगों को जारी एडवाइजरी में कहा कि फर्जी एसएमएस संदेश भेजकर गलत तरीके से दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा प्रस्तुत ऐप से भारत में कोविड-19 टीके के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। एसएमएस के साथ एक लिंक आता है जिस पर क्लिक करने से एंड्रॉयड फोन में संदिग्ध एप इंस्टॉल हो जाता है। यूजर्स को सावधान रहना चाहिए ताकि फर्जी नाम, ई-मेल या मेसेज से आपके डाटा पर हैकर का कब्जा न हो सके। गौरतलब है कि सीईआरटी संघीय तकनीकी इकाई है जो साइबर हमलों से मुकाबला करने के साथ-साथ भारतीय साइबर मंच की रक्षा जासूसी, हैकिंग और अन्य इसी तरह के ऑनलाइन हमलों की पड़ताल करती है।

अज्ञात स्त्रोत से इंस्टॉल होने वाले एप को डिसएबल करें

सीईआरटी ने यह भी सलाह दी है कि यूजर्स अपने फोन की सेटिंग में जाकर किसी अज्ञात स्त्रोत से इंस्टॉल होने वाले एप को डिसएबल की सुविधा इस्तेमाल करें। इसके अलावा भरोसेमंद एंटी वायरस और इंटरनेट फायरवाल जैसे तरीकों का इस्तेमाल करें।

IRDAI ने SBI जनरल इंश्योरेंस पर लगाया भारी जुर्माना, जानें क्या है मामला

बिजनेस डेस्क:

बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने तीसरे पक्ष के मोटर बीमा नियमों का पालन न करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बीमा नियामक ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 2018-19 के संबंधित आईआरडीएआई नियमों में निर्दिष्ट तीसरे पक्ष के मोटर (एमटीपी) बीमा नियमों का पालन नहीं किया। आईआरडीएआई ने कहा कि कंपनी पर आरोप था कि उसने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एमटीपी नियमों का पालन नहीं किया। 2018-19 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दायित्व के अंतर्गत न्यूनतम 638.34 करोड़ रुपए के एमटीपी की जगह केवल 316.36 करोड़ रुपए की अंडरराइटिंग (बीमा) किया। इस तरह कंपनी ने दायित्व से 321.98 करोड़ रुपए कम या 50.44 प्रतिशत की राशि के बराबर का ही एमटीपी किया। आदेश में कहा गया कि कंपनी ने कहा कि उसके अपने व्यापार की किसी भी जगह पर किसी भी एमटीपी नीति की अवहेलना नहीं की और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। इसमें साथ ही यह भी कहा गया कि बीमा कंपनी ने इससे पहले के दो और वित्तीय वर्षों में भी एमटीपी नियमों का पालन नहीं किया था।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

Sports

श्रीलंकाई खिलाड़ी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को ICC ने किया खारिज

दुबई । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के स्वतंत्र भ्रष्टाचार-रोधी पंचाट ने सोमवार को श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अविष्का गुणवर्धने पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया, जिससे उन्हें तत्काल प्रभाव से क्रिकेट से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति मिल गई। गुणवर्धने पर अमीरात क्रिकेट बोर्ड के भ्रष्टाचार के दो आरोप लगे थे। पंचाट ने श्रीलंका के ही नुवान जोयसा के खिलाफ एक आरोप (2.4.6) को बरकरार रखा लेकिन अन्य तीन आरोपों को खारिज कर दिया। आईसीसी के मुताबिक कि इस मामले में विस्तृत फैसला इससे जुड़ी पार्टियों को उचित समय पर भेज दिया जाएगा और इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। गुणवर्धने के खिलाफ धारा 2.1.4 के अंतर्गत आरोप लगाया गया था इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारा 2.1 को तोड़ने का प्रावधान है। उनके खिलाफ धारा 2.4.5 के तहत भी आरोप लगाया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़ी कोशिश को एसीयू को बिना देरी किये सूचित करने का प्रावधान है। जोयसा पर मैच के नतीजे और दूसरे पहलुओं को प्रभावित करने के अलावा एसीयू की जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप है। जोयसा को पिछले महीने छह साल के लिए आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई ने प्रतिबंधित किया था।

जर्मन कप फाइनल : लिपजिग की नजरें पहले खिताब पर

बर्लिन।

मुख्य कोच जूलियन नागेल्समैन के पास आरबी लिपजिग के साथ अब तक का पहला बड़ा खिताब जीतने का मौका होगा, जब उनकी टीम गुरुवार को जर्मन कप के फाइनल में बोरूसिया डॉर्टमंड से भिड़ेगी। 33 साल के जूलियन इस समर में अब बायर्न म्यूनिख के कोच बन जाएंगे। ऐसे में वह जाते जाते अपने खिताब सूखे को समाप्त करना चाहेंगे। जूलियन ने अपने विरोधियों के खिलाफ 11 लीग फाइनल में से अब तक केवल एक ही बार जीता है। डीपीए न्यूज ने जूलियन के हवाले से कहा, रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। यह समय की बात है, जब हम कोई मैच जीते थे। हमारे पास गुरुवार को अगला मौका है। हमें इसे सही से भुनाना होगा। लिपजिग को इससे पहले, जर्मन कप के फाइनल में 2019 में बायर्न म्यूनिख के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, यह एक शानदार अनुभव था, जिसे मैं कभी नहीं भुलूंगा। अब मेरे पास एक और मौका है और मैं इसे विजेता के रूप में समाप्त करना चाहता हूं। डॉर्टमंड के मिडफील्डर जूलियन ब्रैंडट का मानना है कि किसी भी टीम को खिताब का दावेदार नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और यहां कुछ भी हो सकता है।डॉर्टमंड की टीम पिछली बार 2017 में जर्मन कप के फाइनल में पहुंची थी, जहां उसने फ्रैंकफर्ट को 2-1 से हराया था। गुरुवार को टीम अगर जीतती है तो ओवरआल उसका यह पांचवां खिताब होगा।

श्रीलंका के खिलाफ इन दो खिलाड़ियों में से किसी एक को मिल सकती है टीम इंडिया की कप्तानी

नई दिल्ली । श्रेयस अय्यर यदि श्रीलंका के जुलाई में होने वाले सीमित ओवरों के दौरे तक फिट नहीं हो पाते हैं तो फिर अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और आलराउंडर से विशेषज्ञ बल्लेबाज बने हार्दिक पंड्या ही भारतीय कप्तानी की दौड़ में बने रहेंगे। भारत के सीमित ओवरों के विशेषज्ञ श्रीलंका में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय और इतने ही वनडे मैच खेलेंगे। इस दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड में रहेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि श्रेयस श्रीलंका दौरे तक पूरी तरह से फिट हो पाएंगे या नहीं। आम तौर पर इस तरह की चोट के आपरेशन और रिहैबिलिटेशन में लगभग चार महीने का समय लगता है।यदि श्रेयस उपलब्ध रहते हैं तो वह कप्तान पद के लिये स्वतः पसंद होंगे। उनके बाद आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले धवन और मैच विजेता हार्दिक कप्तानी की दौड़ में सबसे आगे हैं। अधिकारी ने कहा कि शिखर का दो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन रहा है जिनमें हाल में स्थगित किया गया टूर्नामेंट भी शामिल है। वह सीनियर बल्लेबाज है और चयन के लिये उपलब्ध रहेगा। वह कप्तानी का मजबूत दावेदार है। इसके अलावा पिछले आठ वर्षों में उसने भारत की तरफ से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां तक हार्दिक का सवाल है तो सीमित ओवरों की क्रिकेट में उनकी मैच विजेता की छवि को कम करके नहीं आंका जा सकता है। उन्होंने कहा कि हां, हार्दिक ने हाल में मुंबई इंडियन्स और भारत की तरफ से गेंदबाजी नहीं की लेकिन वह टीम के लिये तुरुप का इक्का है। प्रभाव छोड़ने वाले खिलाड़ियों में वह अपने साथियों से काफी आगे है। और कौन जानता है कि अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने से वह अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रहे।

कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक को रद्द करने के पक्ष में जापान के लोग

टोक्यो :

जापान की कुल 59 प्रतिशत आबादी टोक्यो में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों को रद्द किए जाने के पक्ष में है। जापान के राष्ट्रीय समाचार पत्र योमिउरी शिंबुन ने व्यक्तिगत तौर पर कराए ताजा सर्वे के आधार पर सोमवार को यह दावा किया है। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते सात से नौ मई के बीच यह सर्वे कराया गया था। इसके मुताबिक जापान के छह प्रांतों के 64 फीसदी लोग ओ लंपिक खेलों को रद्द करने के पक्ष में हैं, जबकि अन्य 41 प्रान्तों में यह औसत 57 फीसदी है। 23 फीसदी लोग चाहते हैं कि खेलों का आयोजन हो, लेकिन उनका मानना है कि दर्शकों के बिना आयोजन होना चाहिए, जबकि 16 फीसदी लोग चाहते हैं कि सीमित संख्या में दर्शकों की मौजूदगी में खेलों का आयोजन हो। मूल रूप से टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इस गर्मियों में 23 जुलाई से आठ अगस्त तक खेलों का आयोजन होना है। उल्लेखनीय है कि गंभीर और खतरनाक हालात के मद्देनजर टोक्यो, ओसाका, क्योटो और ह्योगो प्रांत में 31 मई तक आपातकाल लगा रहेगा। इसके अलावा आइची और फुकुओका में भी आपातकाल लगाया गया है।

WTC फाइनल के लिए भारत का लेग स्पिनर नहीं चुनना थोड़ा चिंता का विषय - कनेरिया

नई दिल्ली।

पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया को लगता है कि भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिये कलाई के स्पिनर का चयन नहीं करके गलती की है तथा राहुल चाहर उनके आक्रमण में नये आयाम जोड़ सकता था। पिछले सप्ताह भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जून से साउथम्पटन में होने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल और चार अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए टीम घोषित की थी। कनेरिया ने कहा कि भारत ने मजबूत टीम का चयन किया है। कुल मिलाकर उनकी टीम अच्छी है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कलाई के स्पिनर का चयन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास रविचंद्रन अश्विन, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के रूप में उंगलियों के स्पिनर हैं लेकिन उनके पास कलाई का स्पिनर दाएं हाथ का लेग स्पिनर नहीं है। इंग्लिश काउंटी एसेक्स की तरफ से खेल चुके कनेरिया ने कहा कि इंग्लैंड की परिस्थितियां लेग स्पिनरों के अनुकूल होती हैं। जब आप इंग्लैंड में खेलते हो तो वहां काफी नमी रहती है। मुझे वहां खेलने का काफी अनुभव है। मैंने विभिन्न परिस्थितियों में आठ साल काउंटी क्रिकेट खेला है। कनेरिया ने कहा कि जब सत्र शुरू होता है तो काउंटी मैच होते हैं। विकेट पर धूप लगती है लेकिन नमी बनी रहती है। जहां भी सीमर के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है वहां लेग स्पिनर भी उपयोगी होता है और इसलिए जब मैं काउंटी क्रिकेट खेलता था तो वहां सफल रहा। इसलिए यह थोड़ा चिंता का विषय है कि भारतीय टीम में कोई लेग स्पिनर नहीं है। उन्होंने कहा कि उंगलियों का स्पिनर अंकुश लगा सकता है लेकिन उंगलियों का स्पिनर और कलाई का स्पिनर होने से टीम पर प्रभाव छोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिनर कनेरिया ने कहा कि राहुल चाहर भारतीय टीम के लिये

उपयोगी साबित हो सकते थे। राहुल चाहर के कद और गेंदबाजी करने के तरीके को देखते हुए उसे टीम में होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के पास ईश सोढ़ी के रूप में लंबे कद का लेग स्पिनर है और विराट कोहली हमेशा लेग स्पिनर के सामने संघर्ष करता है जैसे कि हमने एडम जंपा के मामले में देखा। इसलिए मुझे लगता कि यदि लेग स्पिनर के लिए जगह है तो फिर मुंबई इंडियन्स और भारत की तरफ से अच्छा प्रदर्शन करने वाले चाहर उपयोगी साबित हो सकते थे क्योंकि वह गुगली, फ्लिपर और लेग स्पिन करता है।

संक्षिप्त समाचार

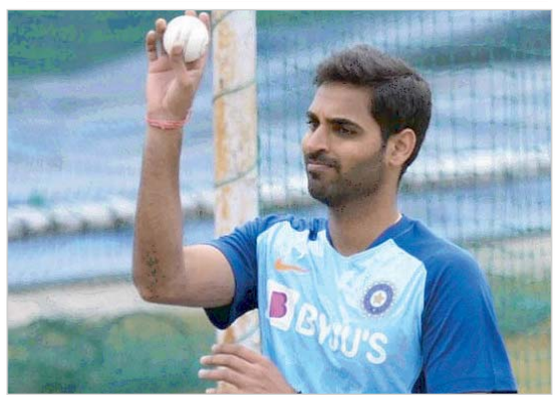

इंग्लैंड दौरे के लिए भुवनेश्वर के ना चुने जाने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा- मैं हैरान नहीं हूं

स्पोर्ट्स डेस्क । इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम का ऐलान किया। ये टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पिनशिप का फाइनल मैच खेलने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस टीम में कुछ खिलाड़ियों को नहीं चुना गया जिसमें भुवनेश्वर कुमार का नाम भी शामिल है। लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता ने कहा कि वह इस बात से हैरान नहीं हैं। भुवनेश्वर को टेस्ट टीम में नहीं चुने जाने पर दासगुप्ता ने कहा, मैं हैरान नहीं हूं। उन्हें पहले ही 6 तेज गेंदबाज (इंग्लैंड दौरे के लिए) मिल चुके हैं। मैं समझता हूं कि वे परिस्थितियां भुवनेश्वर की मदद कर सकती हैं लेकिन उन्होंने 2 से ढाई साल तक लाल गेंद से क्रिकेट नहीं खेला है और अपनी फिटनेस से 2018 से संघर्ष किया है। भुवनेश्वर की फिटनेस पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, आप नहीं जानते कि उनका शरीर 5 दिवसीय क्रिकेट खेल सकता है या नहीं। एक गेंदबाज के रूप में यदि आप खेल रहे हैं तो आपको एक दिन में 20 ओवर फेंकने पड़ सकते हैं और अगले दिन भी वापस आ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप वह चांस लेना चाहते हैं या नहीं। गौर हो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल मुकाबला 18-22 जून के बीच खेला जाएगा जबकि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 4 अगस्त से शुरू होगी और ये 14 सितम्बर को खत्म होगी।

मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कवानी के साथ जारी करार को आगे बढ़ाया

मैनचेस्टर। इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उरुग्वे के फॉरवर्ड एडिंसन कवानी के साथ जारी करार को एक साल और आगे बढ़ाने पर सहमत हो गया है। गोल डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, इस करार के बाद कवानी अब जून 2022 तक मैनचेस्टर सिटी में बने रहेंगे। 34 साल के कवानी हाल के समय में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने पिछले सात मैचों में आठ गोल और तीन असिस्ट किया है। कवानी ने कहा, सीजन के दौरान, मैंने क्लब और जो कुछ भी प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए एक बेहतरीन स्नेह विकसित किया है। मैं अपनी टीम के साथियों और यहां पर्दे के पीछे काम करने वाले स्टाफ के साथ एक गहरा लगाव महसूस करता हूं। वे मुझे हर दिन अतिरिक्त प्रेरणा देते हैं और मुझे पता है कि एक साथ हम विशेष चीजें हासिल कर सकते हैं। कवानी ने इस सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 15 गोल किए है और इनमें से नौ गोल लीग में हुए हैं।

कोरोना से उबरने के बाद बोली भारतीय हॉकी टीम की प्लेयर, मेरा विश्वास नहीं डगमगाया

बेंगलुरु।

कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी तरह से उबरने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की अग्रिम पंक्ति की खिलाड़ी नवजोत कौर ने सोमवार को कहा कि यह खतरनाक वायरस भी आगामी तोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उनके आत्मविश्वास को नहीं डिगा सका है। नवजोत महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल समेत उन खिलाड़ियों में शामिल थीं जो 10 दिनों के ब्रेक के बाद राष्ट्रीय शिविर में वापसी पर कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाई गई थी। सभी खिलाड़ी 14 दिनों तक पृथकवास पर रहने के बाद इससे उबर गई। नवजोत ने कहा, 'जब हमने सुना कि कोविड-19 जांच में हम पॉजिटिव आए हैं तब हमें काफी निराशा हुई। हमारी चिंता यह थी कि सभी प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद भी हम संक्रमित कैसे हो गए।' उन्होंने कहा, 'हम में बीमारी के मामूली लक्षण थे , लेकिन 2 सप्ताह तक पृथकवास पर रहना चुनौतीपूर्ण था।' उन्होंने कहा, 'आज हमने हल्का अभ्यास किया और मैदान पर वापसी करना अच्छा रहा। मैं पृथकवास के दौरान अपने रूम में हल्का अभ्यास करती थी।' उन्होंने कहा, 'इन चुनौतियों से हम अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दे रहे हैं। ओलंपिक खेलों में भाग

लेने वाले सभी एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय है लेकिन लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना महत्वपूर्ण है और इस मामले में हम सबकी यही सोच है।'

सुशील कुमार के खिलाफ आरोपों से भारतीय कुश्ती की छवि को पहुंचा नुकसान : WFI

नई दिल्ली।

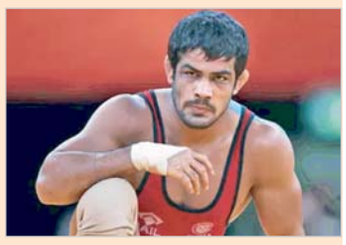

सुशील कुमार जब अपने खेल के शीर्ष पर थे तो उन्होंने अकेले दम पर भारतीय कुश्ती को बुलंदियों पर पहुंचाया लेकिन अब जब पुलिस हत्या के मामले में जब उनकी तलाश कर रही है तो खेल की छवि को भी उतना ही नुकसान पहुंचा है जितना इस पहलवान की छवि को पहुंचा है। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) अब चिंतित हैं क्योंकि इससे खेल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर ने कहा, 'हां, मुझे यह कहना चाहिए कि इससे भारतीय कुश्ती की छवि को बेहद नुकसान पहुंचा है। लेकिन पहलवान मैट से बाहर क्या करते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम मैट पर उनके प्रदर्शन को लेकर चिंतित हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक के साथ ओलंपिक में 56 साल के सूखे को खत्म करने वाले सुशील के खिलाफ पुलिस ने रविवार देर शाम 'लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया क्योंकि यह पहलवान झड़प में युवा पहलवान की मौत के बाद से गायब है। तोमर ने कहा, 'इसने ही नहीं बल्कि फरवरी में हुई घटना ने भी भारतीय कुश्ती की छवि को दागदार किया था। खेल को प्रतिष्ठता हासिल करने के लिए काफी जूझना पड़ा था क्योंकि लंबे समय तक पहलवानों को गुंडों के समूह के रूप में जाना जाता था। तोमर कोच सुखविंदर मोर से जुड़ी घटना का संदर्भ दे रहे थे जो हरियाणा के रोहतक जिले के जाट कॉलेज में साथी कोच मनोज मलिक सहित पांच लोगों की हत्या में शामिला था। सुखविंदर ने कथित तौर पर मलिक के साथ निजी दुश्मनी के कारण पांच लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और बाद में दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर उसे नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

आनंद और चार अन्य ग्रैंडमास्टर कोरोना राहत के लिए खेलेंगे प्रदर्शनी मुकाबले

नई दिल्ली। पांच बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद और चार अन्य भारतीय ग्रैंडमास्टर कोरोना राहत के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से गुरुवार को शतरंज के अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ ऑनलाइन प्रदर्शनी मुकाबले खेलेंगे। आनंद ने कहा, हम सभी को पता है कि भारत कोरोना के कारण किस स्थिति का सामना कर रहा है। ऐसे वक्त में हम सभी किसी ना किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि युवा या वृद्ध में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा होगा जो इससे प्रभावित नहीं हुआ हो। आनंद के अलावा कोनेरु हम्पी, द्रोनावाली हरिका, निहाल सरिन और परागनानंधा रमेशबाबु अन्य चार ग्रैंडमास्टर्स हैं जो इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। आनंद ने कहा, हम सभी को भारत में कोरोना राहत कार्यों के लिए मदद करना होगा। आप भारत के कुछ अच्छे ग्रैंजमास्टर्स में खेल सकते हैं और दान दे सकते है। इस गुरुवार चेकमेट कोविड में भाग लेने के लिए साइनअप करें। शतरंज की तरफ से यह एक छोटा सा योगदान होगा।

बड़ा खुलासा: सुशील कुमार के हाथों में छत्रसाल स्टेडियम का कंट्रोल, करता है प्रताड़ित

स्पोर्ट्स डेस्क ।

ओलंपिक विजेता सुशील कुमार पर पहलवान की हत्या का आरोप है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। इसी बीच सुशील से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम का सारा कंट्रोल सुशील के हाथों में है और उनकी बात ना मानने वालों को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। भारत को सुशील, योगेश्वर, बजरंग और अब तोक्यो के लिए क्वालीफाई कर चुके रवि दहिया और दीपक पूनिया जैसे पहलवान देने वाले छत्रसाल स्टेडियम के सूत्र ने बताया कि योगेश्वर और बजरंग जैसे जाने माने पहलवान यहां से जा चुके हैं क्योंकि बात नहीं मानने के लिए सुशील के समूह ने उन्हें निशाना बनाया। सुशील के कोच और ससुर एशियाई खेल 1982 के चैंपियन सतपाल सिंह 2016 तक स्टेडियम के प्रभारी थे लेकिन इसके बाद वह अतिरिक्त निदेशक के पदक से सेवानिवृत्त हो गए। सूत्र ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा, सुशील को इसके बाद ओएसडी नियुक्त किया गया था और माना जा रहा था कि यह स्टेडियम को परिवार की गिरफ्त में रखने के लिए किया गया। सूत्र ने कहा, 'रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर यहां काम कर रहे सुशील सारे फैसले करते हैं। अगर आप उसकी बात नहीं सुनते या उसके सुझाव के अनुसार काम नहीं करते तो वह धीरे-धीरे आपको प्रताड़ित करना शुरू कर देता है।' उन्होंने कहा, 'लोग कुछ भी कहने से डरते हैं। वे करियर बनाने आते हैं, राजनीति में शामिल होने नहीं। इसलिए स्टेडियम की राजनीति में शामिल होने से आसान उन्हें इसे छोड़कर जाना लगता है। गौर हो कि कुछ दिनों पहले दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम

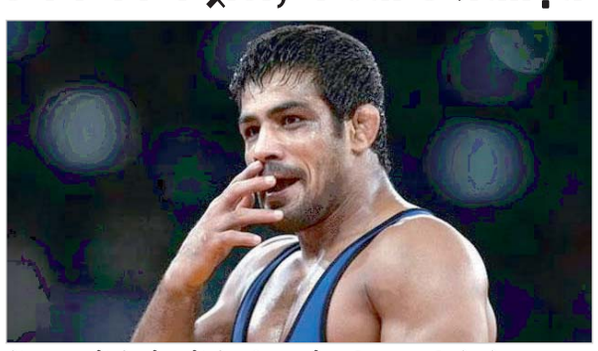

में पहलवानों के दो गुटों के बीच हुए विवाद ने खूनी झड़प का रूप ले लिया था जिसमें 5 पहलवान घायल भी हुए थे।

इसी दौरान एक पहलवान ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था जिसे लेकर कुछ लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और एफआईआर में सुशील कुमार का भी नाम है। लेकिन वह इस घटना के बाद से ही फरार हैं।

डब्ल्यूटीए रैंकिंग में सबालेंका चौथे नंबर पर पहुंची

पेरिस। बेलारूस की एरीना सबालेंका मैड्रिड ओपन का महिला एकल का खिताब जीतने के बाद डब्ल्यूटीए की विश्व रैंकिंग में सातवें से चौथे नंबर पर पहुंच गई हैं। सबालेंका ने रविवार को दुनिया की नंबर-1 महिला टेनिस खिलाड़ी आस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी को हराकर मैड्रिड ओपन का महिला एकल खिताब जीता है। उनके करियर का यह 10वां और चौथा डब्ल्यूटीए 1000 खिताब है। इससे पहले वह वुहान में (2018 और 2019) तथा दोहा में डब्ल्यूटीए 1000 खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। सबालेंका ने कहा, यह अविश्वनीय है। मैं वास्तव में इस सुधार से खुश हूं। अभी भी बहुत सी चीजें सुधारनी बाकी हैं। हां, बेशक, मैं वास्तव में खुश हूं, लेकिन मैं वास्तव में रैंकिंग पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही हूं। मैं अपने खेल पर ज्यादा ध्यान दे रही हूं। यह नंबर 4, नंबर 1 नहीं है। इसलिए अभी भी बहुत सी चीजों पर काम करना है और सुधार करना है। सबालेंका डब्ल्यूटीए रैंकिंग के इतिहास में टॉप 5 में पहुंचने वाली वाली बेलारूस की दूसरी खिलाड़ी है। उनसे पहले विक्टोरिया एजारेंका नंबर वन रैंकिंग हासिल कर चुकी है।

2 रिश्तेदारों की मौत पर भड़कीं मीरा चोपड़ा , बोलीं-

कोरोना ने नहीं, सरकार की नाकामी ने मारा

कोरोनावायरस की दूसरी लहर ने देश में तहलका मचा दिया है। इस वायरस की वजह से हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। बॉलीवुड और टीवी के बहुत से सितारें भी इस महामारी की वजह से अपनो को खो चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा की कजिन एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा ने भी पिछले 10 दिनों में अपने परिवार के 2 सदस्यों को खो दिया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि उनके परिवार के दो सदस्यों का निधन हो गया है। अब मीरा का कहना है कि उनके परिवार के लोगों को कोरोनावायरस ने नहीं बल्कि देश की कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था ने मारा है। मीरा चोपड़ा ने कहा, मैंने कोविड-19 की वजह से अपने दो करीबी कजिन को नहीं खोए बल्कि खराब स्वास्थ्य सेवाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेरे पहले कजिन को करीब दो दिन तक बेंगलुरू में आईसीयू बेड नहीं मिला और दूसरे का ऑक्सीजन लेवल अचानक कम हो गया था। दोनों की उम्र 40 साल के आस-पास थी। उन्होंने बताया है कि वह इस घटना के बाद से काफी डरी हुई हैं। उन्होंने कहा, यह बहुत दुखद है कि हम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। मैं लगातार डर के साथ हूं कि अब आगे क्या होगा। हर एक जिंदगी बस खत्म होती दिख रही है। आप अपनी क्षमता के साथ सबकुछ करते हैं लेकिन आप फिर भी उन्हें खो देते हैं। मीरा ने कहा, बहुत गुस्सा आ रहा है और ऐसा पहली बार है जब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा देश कूड़ेदान में चला गया है। हम अस्पताल में ऑक्सीजन, इंजेक्शन, दवाइयों और बेड्स की व्यवस्था नहीं कर पाए। सरकार हमारे लिए यह सब करती है लेकिन वो हमारे लोगों की जिंदगियां बचाने में विफल रही। उन्होंने कहा, पिछले साल लॉकडाउन लगा था ऐसे में महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जा सकता था लेकिन दूसरी लहर के साथ पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। मुझे यह भी पता नहीं है कि मैं अब क्या महसूस कर रही हूं। परिवार में पिछले 10 दिनों में हुई दो मौतों के बाद अब मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती है।

कोरोना काल में जरूरतमंदों को फूड डोनेट कर रहे फरहान अख्तर

देश में कोरोनावायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। वहीं संकट की इस इस घड़ी में कई सेलेब्स मदद के लिए आगे आ रहे है। अभिनेता-फिल्म निर्माता फरहान अख्तर भी उत्तर प्रदेश के शहर में कोविड प्रभावित परिवारों और देखभाल करने वालों की मदद में आगे आए हैं। मीडिया की लाइमलाइट से दूर फरहान ने नॉन-फॉर-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन- होप फॉर वेलफेयर ट्रस्ट के साथ काम करना जारी रखा है। उनके दान का उपयोग इस मुश्किलभरे हालात में रोगियों और देखभाल करने वालों को खाना खिलाने के लिए किया जा रहा है।

एनजीओ के सेक्रेटरी दिव्यांशु उपाध्याय ने साझा किया कि इन दान का उपयोग न केवल वायरस संक्रमित रोगियों को खाना खिलाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि वाराणसी में हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका शमशान घाटों पर काम करने वाले लोगों के लिए भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि होप टीम में से आठ लोग शहर में हर दिन 1000 थालियों का वितरण कर रहे हैं। प्रत्येक थाली में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद और बिस्कुट हैं। यदि हम दिन में अस्पतालों में भोजन वितरित करते हैं, तो रात में श्मशान घाट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फरहान सर हमेशा हमारी जरूरत के समय में हमारे साथ खड़े रहे हैं और हम इन कठिन वक़्त में उनके योगदान के लिए आभारी हैं। एनजीओ सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से फरहान तक अपनी आवाज़ उस वक़्त पहुंचाई थी जब शहर में कोविड के मामलों में वृद्धि देखने मिली और अभिनेता तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मदद करने के लिए तैयार थे। फरहान ने संकट में फंसे लोगों के कल्याण के लिए गुप्त रूप से और सक्रिय रूप से योगदान दिया है। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज और एनआईएस क्वालिफाइड कोच की मदद की थी, जो कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पिछले साल, उन्होंने सरकारी अस्पतालों के हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए 1000 पीपीई किट वितरित की थी।

अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के एक कोविड केयर सेंटर को दो करोड़ दिए दान

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में शुरू किए गए श्री गुरु तेग बहादुर कोविड देखभाल केन्द्र को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए दो करोड़ रुपये दान दिए हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मंजिंदर सिंह सिरसा ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। सिरसा ने रविवार को ट्वीट किया, '' 'सिख महान है, उनक सेवा को सलाम,' अमिताभ बच्चन जी ने श्री गुरु तेग बहादुर कोविड देखभाल केन्द्र को दो करोड़ रुपये का योगदान देते समय यह शब्द कहे।'' उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, बच्चन हर दिन केन्द्र में चल रहे काम के बारे में पूछते थे। मध्य दिल्ली के गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में सोमवार दोपहर से 300 बिस्तर वाले गुरु तेग बहादुर कोविड देखभाल केन्द्र को खोला गया है। अन्य एक ट्वीट में सिरसा ने बताया कि 78 वर्षीय अभिनेता ने इस केन्द्र के लिए विदेश से ऑक्सीजन सिलेन्डर भी मंगवाए हैं। उन्होंने कहा, '' वह केवल बड़े पर्दे के ही नहीं असल जिंदगी में भी एक नायक हैं।'' बच्चन ने रविवार को प्रसारित किए गए 'वैक्स लाइव- द कंसर्ट टू रियुनाइट द वर्ल्ड' के दौरान वैश्विक समुदाय से वैश्विक महामारी की दूसरी लहर की मार झेल रहे भारत की मदद करने की अपील की थी। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को कोविड-19 के 13,336 नए मामले सामने आए और संक्रमण से 273 और लोगों की मौत हुई।

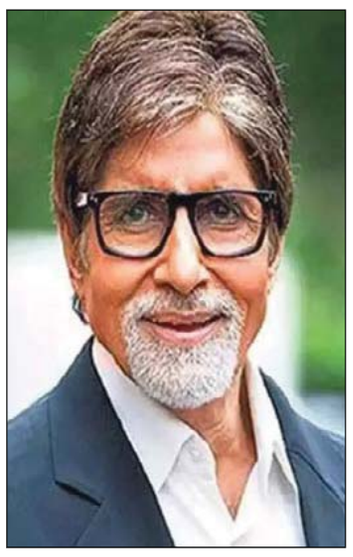

24 घंटे में इतने हजार लोगों ने मांगी सोनू सूद से मदद

एक्टर बोले- सब तक पहुंचने में लग जाएंगे 14 साल

देश में कोरोनावायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। महामारी के इस दौर में कई सेलेब्स मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी हरसंभव लोगों की मदद कर रहे हैं। सोनू सूद से हर दिन हजारों लोग सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रहे हैं। ऐसे में सोनू सूद के पास एक दिन में इतनी मदद की अपील आई कि उनका हर किसी तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। सोनू अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक का इंतजाम कर रहे हैं। इसके अलावा वे किसी भी तरह की मदद मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सोनू सूद ने ट्वीट किया, 'कल (शनिवार) मुझे लगभग 41660 रिक्वेस्ट आईं। हम इन सभी तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो हम नहीं कर सकते। अगर मैं इन सभी तक पहुंचने की कोशिश करूंगा तो मुझे 14 साल लग जाएंगे जिसका मतलब है 2035।' बता दें कि बॉलीवुड से लगातार सेलेब्स की कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं। बीते कुछ हफ्तों में कई बड़े-बड़े सेलेब्स इस जानलेवा वायरस के चपेट में आ चुके हैं। सोनू सूद भी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं।

सुनी-सुनाई बातों पर भेजे जाने वाले मैसेज से रहें सावधान

फिल्म निर्माता और लेखक विक्रम भट्ट का कहना है कि हम सभी को ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स और उन लाखों फॉरवर्ड मैसेज से सावधान रहना चाहिए, जो सुनी-सुनाई बातों के आधार पर कोविड से संबंधित उपचार और निवारक उपायों के बारे में बताते हैं। विक्रम ने कहा, यहां पर बहुत सारी गलत जानकारी होती है। इस गंभीर परिदृश्य में जो चीज मुझे खुश करती है, वह यह है कि जिस तरह से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अजनबी एक- दूसरे तक पहुंच रहे हैं। विक्रम भट्ट ने सोशल मीडिया के अन्य फायदे गिनवाते हुए कहा कि इसके माध्यम से ऑक्सीजन लंगर, फूड प्रोवाइडर (खाद्य प्रदाता), स्वयंसेवकों की पहुंच सुनिश्चित होती है और यही वास्तविक भारत है। विख्यात फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा, ''हमने इसकी एक झलक देखी थी, जब जुलाई 2005 में मुंबई को एक जलप्रलय का सामना करना पड़ा था। मानवता और विज्ञान की यह भावना वायरस को हरा देगी।'' दरअसल, अभिनेत्री सनी लियोन के पति डैनियल वेबर द्वारा एक इंस्टाग्राम लाइव सीरीज होस्ट की गई थी, जिसमें भट्ट इस संकट की घड़ी में लोगों के लिए सकारात्मक रहने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। उन्होंने इस लाइव सीरीज के दौरान अपने विचार रखते हुए यह बातें कही। विक्रम की बेटी कृष्णा भी चैट में शामिल हुईं।

डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं समीरा रेड्डी

बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वह अक्सर अपनी लाइफ से जुड़ी बातें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। हाल ही में मदर्स डे पर समीरा ने अपनी प्रेग्नेंसी, इस दौरान आए बदलाव, विचारों और लोग क्या कहेंगे वाली बातों सहित कई मुद्दों पर विचार प्रकट किए हैं। समीरा का कहना है कि जब प्रेग्नेंसी में उनका वजन 105 किलो हो गया था। ऐसे में जब अपने बेटे को गोद में लिया तो खुशी नहीं हुई। समीरा ने कहा, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने सोचा था कि मैं उन पेज 3 मॉम्स की फोटोग्राफर्स को पोज दूंगी एक परफेक्ट बंप के साथ। मेरे मातृत्व का विजन ग्लैमर वर्ल्ड से था। लेकिन 9 महीने बाद, मेरा वजन 105 किलोग्राम हो गया। उन्होंने कहा, जब मैंने मेरे सुंदर बेटे को गोद में लिया, मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। मैं बच्चे के जन्म के बाद होने वाले डिप्रेशन में चली गई। इसी बीच उनके पति अक्षय ने बच्चे के डायपर चेंज करने से लेकर सबकुछ किया। एक्ट्रेस कहती हैं, मैं यही सोचती थी कि दूसरी एक्ट्रेसेस कैसे एक महीने में ही काम कर लौट जाती हैं। मेरी सास कहती रहती थीं, तुम्हारा बेबी स्वस्थ है, तुम्हारा पति कितना सपोर्ट करता है... तुम अपसेट क्यों हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुई, मैं घर आई और जोर—जोर से रोई। ये भी ग्लानि थी कि मैं मेरे बेटे के लिए वहां नहीं थी। समीरा ने कहा, ये एक साल तक चला। तब तक मैं फिल्म इंडस्ट्री से कट चुकी थी। मेरा वजन उतना ही था 10 किलोग्राम और उस समय, मैं एलोपेसिया एरेटा (तेजी से बाल झड़ने का रोग) से डायग्नोस की गई। बालों के गुच्छे मेरे सिर से झड़ते थे। तब एक्ट्रेस को महसूस हुआ कि उनकी समस्या ज्यादा गहरी थी। उन्हें हकलाने, वजन ज्यादा होने, दो प्रतिभाशाली बहनों के साथ बड़ा होने और उसे इंडस्ट्री के प्रेशर से पार पानी थी जो आपकी लगातार स्क्रूटनी करती है। समीरा ने कहा, तब भी, एजेंसीज मुझसे पूछतीं कि क्या आप यम्मी मम्मी बनेंगी, या एक योगा मम्मी बनेगी या फिर वही 'सेक्सी सेम' बनेंगी। लेकिन मैंने तय किया कि मैं फॉलोअर्स बनाने के लिए झूठी जिंदगी नहीं जिउंगी।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

गांव में करियर की छांव

गांवों के इस देश में बाजार और सरकार, दोनों की नजर ग्रामीण क्षेत्रों पर है। सरकार जहां गांवों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास की लहर चलाना चाहती है, वहीं बाजार अपना उत्पाद खपाने की रणनीति आए दिन अख्तियार कर रहा है। इन सबके बीच गांव के किसान भी आज बाजार से सीधे-सीधे तालमेल बैठा कर अपना माल बेचना चाहते हैं। वह कंपनियों और बाजार से संपर्क साध कर ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूलने की रणनीति अपनाते हैं।

प्रतिस्पर्धी माहौल में विकास और बाजार की योजनाओं को सफल बनाने के लिए आज योजनाकार से लेकर कुशल प्रबंधकों की खासी जरूरत है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि समझ कर ही किसी भी योजना को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, जैसे कुछ दशक पहले ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए दुग्ध क्रांति की शुरुआत की गई। इसके तहत दूध और डेयरी उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। यह योजना पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में काफी सफल रही। इसमें किसानों को आय का जरिया प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक मजबूती प्रदान की गई। दुग्ध क्रांति की तरह ही योजनाकारों ने हरित क्रांति का आगाज किया। इसमें भी कम लागत में उन्नत बीज के जरिए खाद्य पदार्थों की पैदावार में बढ़ोत्तरी की गई। उत्तरी भारत के कई राज्यों ने इसमें अभूतपूर्व सफलता हासिल की। इसका लाभ सीधे किसानों को मिला और देश को भी। विदेशों से अनाजों का आयात घटा और अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता आई। आयात कम होने पर देश का पैसा बाहर जाने से रुका।

ग्रामीण विकास का यह नजारा रातोरात नहीं दिखा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में है। आज कृषि के कमर्शियलाइजेशन से लेकर ई-विलेज तक की कल्पना को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा चुके हैं। कमोडिटी एक्सचेंज के कारण अब किसानों की फसलों के दाम रोज बदल रहे हैं और उसी आधार पर किसान फसल बेच भी रहे हैं। विकास की इस निरंतरता को बनाए रखने या उसे सही दिशा देने के लिए आज ऐसे प्रोफेशनल्स और प्रबंधकों की जरूरत विशेष तौर पर पड़ रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास, गरीब और दलित लोगों के उत्थान, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम कर सकें। ग्रामीण स्वास्थ्य की देखभाल, वहां संचार का विस्तार, सामाजिक विकास, भूमि सुधार और उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य कर सकें। विशेषज्ञों के मुताबिक ग्रामीण विकास की योजना में पहले कल्याण और चैरिटी की भावना से काम किया जाता था, अब विकास और ग्रामीण आबादी को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए किया जाता है। निजी कंपनियां ऐसी जगहों पर लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने और अपने उत्पाद को खपाने के नजरिए से काम करती हैं। टाटा, रिलायंस और कई उद्योग व संचार से जुड़ी कंपनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने विशेष यूनिट बनाए हैं, जिनके लिए उन्हें दक्ष प्रबंधकों और सक्षम लोगों की जरूरत है। उत्पादन के अलावा सरकार द्वारा सामाजिक विकास के लिए तैयार की गई कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए भी कुशल प्रबंधन की जरूरत है। इस काम में विशेषतौर पर प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने गुजरात के आनंद में इरमा यानी इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ ग्रामीण प्रबंधन नाम से संस्थान भी स्थापित किया। संस्थान अपने यहां इस काम के लिए प्रोफेशनल तैयार करता है। इरमा के अलावा देश के अन्य संस्थानों ने भी ग्रामीण विकास में दक्ष लोगों की जरूरत को देखते हुए डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए हैं, जो आज जगह-जगह चलाए जा रहे हैं।

किस-किस तरह के कोर्स

ग्रामीण विकास और उससे जुड़े प्रबंधन के काम को समझने और उसमें दक्षता हासिल करने के लिए आज सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा, एमबीए और एमए जैसे कोर्स विभिन्न संस्थानों में चल रहे हैं। सर्टिफिकेट कोर्स में मुख्य तौर पर ग्रामीण विकास की आधारभूत जानकारी दी जाती है। उसके विविध पहलुओं से रूबरू कराया जाता है। पीजी डिप्लोमा लर्नर को इस क्षेत्र की योजना, कार्य, उसके निरीक्षण और मूल्यांकन का हुनर सिखाता है। एमए ग्रामीण विकास में भारतीय परिप्रेक्ष्य, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, योजना और प्रबंधन, रिसर्च पद्धति और डिजर्टेशन आदि का पाठ पढ़ाया जाता है। एमबीए जैसे कोर्स छात्रों में मानव मनोविज्ञान, बिहेवियरल साइंस और प्राकृतिक संसाधनों की समझ पैदा करता है। उन्हें ग्रामीण विकास के सिद्धांत मसलन ग्रास रूट लर्निंग, संस्कृति और काम करते हुए सीखने पर बल देता है। वह विकास की योजनाओं के बीच प्रबंधन की कला सिखाता है। उन्हें क्षेत्र विशेष पर प्रोजेक्ट करने को भी देता है। देश के मैनेजमेंट संस्थानों और प्रमुख विश्वविद्यालयों में इससे जुड़े कोर्स बखूबी चल रहे हैं। इन संस्थानों में प्रमुख हैं।

इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद व कोलकाता
इंस्टीटयूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट यानी इरमा, आनंद
नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद
नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद
इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, जयपुर
टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंस, मुम्बई
सेंट जेवियर इंस्टीटयूट ऑफ सोशल सर्विस आदि।

विश्वविद्यालयों में इग्नू ग्रामीण विकास में पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और एमए तीनों तरह के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी हिन्दी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी एमए स्तर का कोर्स चलाया जा रहा है।

रोजगार के रास्ते

रूरल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट से जुड़े कोर्स करने के बाद छात्रों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में काम करने के अवसर मिलते हैं। सरकारी एजेंसी के विभिन्न विभागों और राज्य स्तरीय सेंटरों में काम करने का मौका मिलता है। संस्थानों में ट्रेनर, रिसर्चर, कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट को-कॉर्डिनेटर जैसे पदों पर काम करने का अवसर है। वे चाहें तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से जुड़ी स्कीम और कार्यक्रमों को ठेके पर भी कर सकते हैं। प्रतिभाशाली युवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे जुड़ी विशेष एजेंसियों में काम करने के अवसर हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठन अपने यहां ग्रामीण प्रबंधक के रूप में ऐसे लोगों की नियुक्ति करते हैं, जो गांवों में विकास की योजना को अंजाम तक पहुंचा सकें। ऐसे प्रबंधक चाहे तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना एनजीओ खोल सकते हैं। रिसर्च और किसी प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले बैंक भी अवसर मुहैया करा रहे हैं।

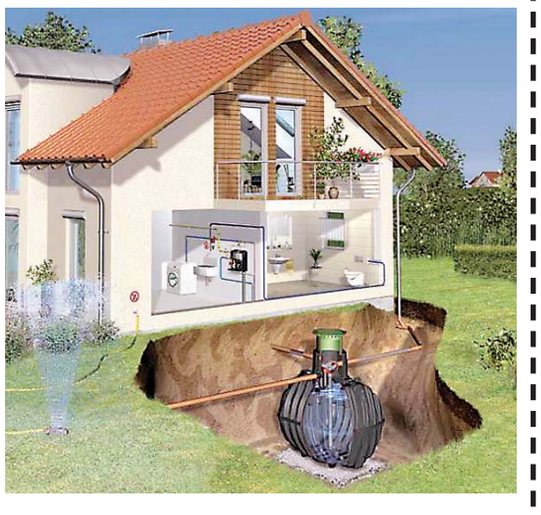

गाइडेंस एंड काउंसलिंग

दूसरों की सहायता में करियर

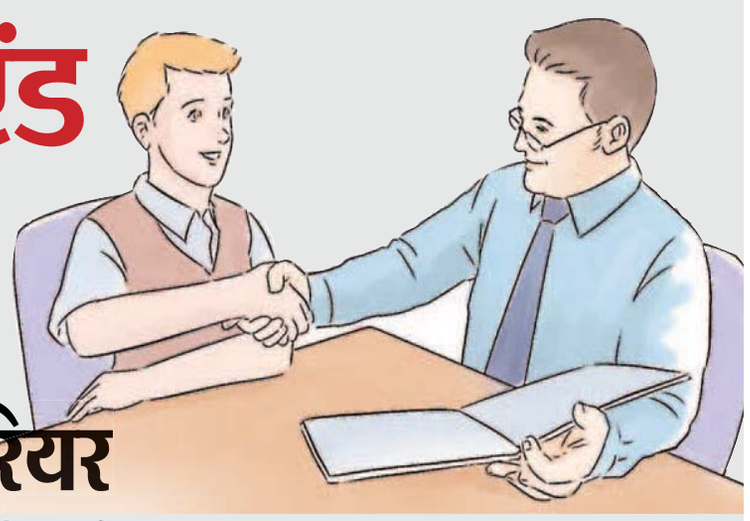

छात्रों और प्रोफेशनल्स को ही नहीं आजकल वैवाहिक मामलों, बाल व समाज सुधार केंद्रों और अस्पतालों तक में गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत महसूस हो रही है। इसी कारण इन जगहों पर काउंसलरों की भर्ती तेजी से की जा रही है। इससे इस नए करियर की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है।

गाइडेंस और काउंसलिंग किसी भी विद्यार्थी या व्यक्ति को दी जाने वाली वह सहायता है, जिसके सहारे वह खुद को व दूसरों को समझता है और एक बेहतर जिंदगी या करियर के लिए खुद को तैयार करता है। इस प्रक्रिया में वह अपनी जरूरतों व महत्त्वाकांक्षाओं में तालमेल बिठाना सीखता है और हर माहौल व चुनौती के लिए अपने कौशल को निखारने का यत्न करता है। इस लिहाज से मार्गदर्शन या परामर्श किसी को अपनी समस्याओं से निबटने में उन विकल्पों की राह खोलता है, जिसके सहारे अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि व्यक्ति भविष्य के लिए खुद को तैयार करता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग से अपनी रुचि को पहचानने में मदद मिलती है, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानने का अवसर मिलता है और इनके हिसाब से अपना भविष्य चुनने में आसानी होती है। इसका लाभ यह है कि आप पर कुछ भी थोपा नहीं जा सकता या फिर आप किसी की देखा-देखी करने में यकीन करना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको अपनी योग्यता व कमजोरी का पता है। इसके अलावा, परामर्श से किसी उलझन या परेशानी या किसी ऐसी रुकावट को दूर करने में मदद मिलती है, जिसके कारण विकास का रास्ता रुका हुआ होता है। इसे और सरल तरीके से समझा जाए तो कहा जा सकता है कि बारहवीं करने के बाद आप यदि तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लूं तो काउंसलर की मदद ले सकते हैं। वह आपकी काबिलियत व पसंद के हिसाब से आपको बताएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। लेकिन यदि आप खुद गाइड व काउंसलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी पाठ्यक्रम हैं, जो इसकी बारीकियों को समझने में मदद करेंगे और आप दूसरों को रास्ता दिखा सकेंगे तथा उनकी परेशानियां दूर कर पाएंगे।

क्या है इसके पीछे का दर्शन

गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, वे कमोबेश हर देश में एक जैसे हैं। स्थानीय मान्यताओं व विश्वासों के साथ तालमेल बनाना पड़ता है। इसके आठ सिद्धांत इस प्रकार हैं -

हर व्यक्ति की मर्यादा अहम होती है। हर व्यक्ति एक-दूसरे से जुदा-जुदा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व को निखारना होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी समझ और सोच के हिसाब से ही काम करता है। कोई भी व्यक्ति खुद को जैसा मानता है, उसी हिसाब से अपने को निखारने की कोशिश करता है।

हर व्यक्ति में सीखने की क्षमता होती है और वह अपने विकल्प चुन सकता है। हर किसी को निरंतर मार्गदर्शन की जरूरत होती है।

किसी को भी उसके मुताबिक सक्षम सलाहकारों की मदद की जरूरत पड़ सकती है।

कोर्स एवं योग्यता

गाइडेंस एंड काउंसलिंग के सिद्धांतों को जानने-समझने के लिए पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। यह कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये कोर्स एक वर्ष के हैं। इनके लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। पाठ्यक्रम में व्यक्तित्व, व्यवहार, अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत अंतर, आकलन जैसे विषयों को पढ़ाया जाता है। विजन इंस्टीटयूट के डायरेक्टर मुकेश गुप्ता के मुताबिक ये पाठ्यक्रम समाज की जरूरत हैं। शिक्षकों, पेशेवरों, पुनर्वास कार्यकर्त्ताओं, विशेष शिक्षकों इत्यादि के लिए यह जरूरी है कि वे इसका महत्त्व समझें और शिक्षा में इसे शामिल करें, ताकि हर विद्यार्थी को उसकी काबिलियत के हिसाब से मंजिल मिल सके।

कहां-कहां हैं अवसर

पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स करने के बाद रोजगार के कई विकल्प हैं, जैसे स्कूलों, अस्पतालों, पुनर्वास केंद्रों, बाल सुधार केंद्र, करियर काउंसलिंग केंद्रों, क्लिनिकों, बाल एवं युवा परामर्श केंद्रों, वैवाहिक परामर्श केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों में अवसर ही अवसर हैं। पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स करने के बाद अपने देश में सरकारी और गैर सरकारी विभागों में रोजगार के अलावा विदेशों में भी बेशुमार अवसर हैं।

रेन वॉटर हारवेस्टिंग

जल संचय से करें धन संचय

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून.. आज आम इंसान को पानी की कीमत का अंदाजा हो या न हो, लेकिन चार-पांच सौ साल पहले रहीम ने अपने दोहे के माध्यम से जो यह अनमोल बात कही है, उसे हम सबको आज के संदर्भ में बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जनसंख्या विस्फोट की वजह से आज औद्योगिकीकरण और शहरीकरण में तो बढ़त हो ही रही है, खाद्य पदार्थों और जल की मांग भी लगातार बढ़ रही है और हालात यह है कि एक तरफ तो नदियों में बाढ़ आ रही है और दूसरी तरफ भूमि का जलस्तर लगातार घट रहा है। यह कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले पचास-सौ सालों में लोग भूमिगत जल के लिए तरस जाएं और जलापूर्ति के लिए इंसान को भी नदियों/पोखरों का सहारा लेना पड़े। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार-'पृथ्वी का जलस्तर औसतन तीन से चार फुट प्रतिवर्ष गिर रहा है।' ऐसे में इस सबसे बचने के लिए वर्षा जल संचयन यानी रेन वॉटर हारवेस्टिंग धन संचय जैसा है। दिल्ली जैसे शहर में जहां लगभग दस ग्यारह महीने पानी की किल्लत रहती है, वहीं जरा-सी बारिश होने पर जल भराव, ट्रैफिक जाम, सड़क धंसने जैसी तमाम किल्लतें खड़ी हो जाती हैं। बेशक आज सरकार वर्षा जल संचयन के नाम पर विज्ञापन में करोड़ों रुपये खर्च कर रही हो, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने तथा उन्हें बारिश के जल को स्टोर करने के तौर-तरीके सिखाने का काम आप कर सकते हैं। इससे आप अपना भविष्य तो संवार ही सकते हैं, साथ ही समाज को जल ही जीवन है की सोच भी दे सकते हैं और लोगों को जल की किल्लत से बचा कर भविष्य में आने वाली कठिनाइओं से बचा सकते हैं। इसके लिए इग्नू द्वारा सर्टिफिकेट इन वॉटर हारवेस्टिंग एंड मैनेजमेंट यानी सीडब्ल्यूएचएम नाम का छह महीने का कोर्स करवाया जाता है। अनेक प्राइवेट संस्थान भी वर्षा जल संचयन के कोर्स करवाते हैं, जिनमें से सेन्टर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट भी एक है।

योग्यता

इग्नू से वर्षा जल संचयन और प्रबंधन का सर्टिफिकेट कोर्स को करने के लिए कम से कम दसवीं पास होना आवश्यक है। यदि किसी ने इग्नू से बीपीपी कोर्स किया है तो भी अभ्यर्थी इस कोर्स को कर सकता है।

आवेदन कैसे करें

इच्छुक अभ्यर्थी अपने नजदीकी इग्नू संस्थान में जाकर सौ रुपये का प्रॉस्पेक्टस यानी विवरणिका लेकर उसमें दिए गए फार्म को पूर्णतया भर कर आवश्यक दस्तावेजों तथा शुल्क के साथ जमा करा सकते हैं।

समयावधि

सीडब्ल्यूएचएम कोर्स की अवधि छह माह है, लेकिन अभ्यर्थी इसे अधिक से अधिक दो वर्ष में पूरा कर सकता है।

माध्यम

इग्नू में इस कोर्स के हिन्दी व अंग्रेजी, दोनों ही माध्यम मौजूद हैं। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चुनाव कर सकता है।

अवसर

इस कोर्स को करने के बाद अभ्यर्थी सरकारी/गैर सरकारी, दोनों प्रकार की नौकरी के लिए योग्य हो जाता है। वह भू-संपत्ति, मृदा संरक्षण, भू-जल बोर्ड, शहरी आवास बोर्ड, मौसम विभाग आदि में आवेदन कर सकता है। इसके साथ अपना स्वयं का इंस्टीटयूट खोल कर भी लोगों को शिक्षा दे सकता है।

छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विकलांग/ शहीद आश्रित/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध है। पात्र विद्यार्थी अपने नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय अथवा अधिकारी से आवेदन पत्र लेकर भर सकते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म

सचिन GIDC में एक मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया, चप्पू से धमकाया

क्रांति समय दैनिक

सूरत, सचिन जीआईडीसी क्षेत्र में रहने वाले एक श्रमिक वर्ग के परिवार की चार वर्षीय बच्ची कल रात अपने घर के पास छत पर खेल रही थी जब पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसे अगवा कर लिया और उसे अपने कमरे में ले गया जहाँ उसने उसे बांध दिया। उसे चप्पू से धमकाया। पीड़िता बच्ची के शरीर पर खून निशान दिखाई देने से माता-पिता सहित परिवार वाले इस घटना से स्तब्ध थे, जबकि स्थानीय लोग भी गुस्सा में पकड़ कर पुलिस को जानकारी दी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया

पुलिस सूत्रों के अनुसार, GIDC क्षेत्र की ४ वर्षीय एक लड़की सचिन अपने भाई के साथ रात लगभग 9:30 बजे घर के सामने एक मकान की छत पर खेल रही थी, जब पड़ोसी नरधाम सोनू उर्फ बंटी रमाशंकर वर्मा ने उसका अपहरण कर लिया। लड़की और उसे अपने कमरे में ले गई। जब लड़की रोने लगी, तो नारदम ने उसे एक चप्पू दिखाया, जिससे वह डर गया और उसके साथ दुराचार किया। लड़की रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग वहां जमा हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे और कमरे का दरवाजा खोला और सभी चौकी गए जहां लड़की खून से लथपथ हालत में मिली थी। जब पुलिस ने नारधम को वहां से भगाया तो इस घटना के बाद इलाके में हंगामा मच गया। लड़की की हालत ऐसी हो गई है कि उसे सिविल हॉस्टल में भर्ती कराना पड़ा। जब पुलिस ने नारद सोनू उर्फ के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया। घटनाक्रम की आगे की जांच पुलिस कर रही है

भाजपा विधायक की कोरोना से मृत किसान और खेत मजदूरों के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग

क्रांति समय दैनिक

जामनगर ग्रामीण क्षेत्र से भाजपा विधायक राघवजी पटेल ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पत्र लिखकर कोरोना से मृत किसान और खेत मजदूरों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है।

पटेल ने पत्र में लिखा है कि कोरोना काल में किसान और खेत मजदूरों की हालत काफी दयनीय हो गई है और ऐसे में सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। गुजरात में किसानों के लिए लागू दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसान और खेत मजदूरों के परिवार को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

राघवजी पटेल ने पत्र में लिखा कि कोरोना का अन्य व्यापार-उद्योग की भांति कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल असर हुआ है।

ग्रामीण इलाकों मंस तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की वजह से ग्रामीण अर्थ तंत्र चरमराने लगा है।

ऐसे हालात में जिन किसानों या खेत मजदूरों की कोरोना से मौत हुई है,

उनके परिजनों को किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभार्थी मानकर राज्य सरकार आर्थिक मदद करे।

गुजरात में प.रे. की ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने वाले लोको पायलट ने कहा राष्ट्रहित में योगदान देना बड़े गर्व की बात

क्रांति समय दैनिक

अहमदाबाद,देश भर के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने के भारतीय रेलवे के प्रयासों को गति देते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा कोविड के खिलाफ संयुक्तजंग को मजबूती प्रदान करने तथा कोविड मरीजों और उनके परिवारों को राहत प्रदान के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) के परिवहन के लिए लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं। पश्चिम रेलवे में गुजरात से हापा व मुंद्रा पोर्ट से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट ने अपने अनुभव साझा किए। अहमदाबाद मंडल के गांधीधाम में पदस्थ लोको पायलट सर्वेश शर्मा बताते हैं कि मेरी २१ वर्ष की सेवा अवधि की यह यादगार यात्रा रही है जब मुझे मुंद्रा पोर्ट कार्गो कॉम्पलेक्स से पाटली (हरियाणा) के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के लिए ड्यूटी कॉल आया। उस वक्तमें परिवार के साथ था तथा घर पर भी पत्नी पर बच्चों में इस ड्यूटी के लिए उत्साह नजर आया क्योंकि समाचार पत्रों वह टीवी पर देख रहे थे कि हमारे यहां ऑक्सीजन की कमी है एवं भारतीय रेलवे इस प्राणवायु की निरंतर आपूर्ति दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश को कर रही है। उस यात्रा के लिए मैं भी माध्यम बन रहा था। उन्होंने बताया कि ८४ टन लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर के ०६ कंटेनर सहित पूरी ट्रेन के साथ पालनपुर तक की यात्रा में कोई बाधा नहीं रही। हमने इस ट्रेन को राजधानी ट्रेन की गति से दौड़ाया। हर स्टेशन पर हमें ग्रीन सिगनल मिला तथा ३७२ किलोमीटर की यह दूरी हमने ०६ः४५ घंटे में पार की जो कि डबल स्टैक कंटेनर रेक के लिए अधिकतम रही तथा मैंने भी अभी तक की सर्वाधिक लंबी ट्रेन चलाने का आनंद लिया। राजकोट डिविजन के लोको पायलट अरुण कुमार पांडे ने बताया कि उन्होने ४ मई, २०२१ को हापा से सुरेन्द्रनगर के बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलायी। इस दौरान उन्हे इस सेक्शन में सभी जगह ग्रीन सिग्नल मिले जिससे कि वो ट्रेन को सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए लगभग ५३-५६ किमी प्रति घंटे की औसत गति से निर्बाध पथ पर चला सके। उन्होने कहा ''वर्तमान परिस्थितियों में जब देश में कोविड-१९ के चलते देश के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है , ऐसे समय में ऑक्सीजन पहुंचाने के भारतीय रेलवे के इस मिशन का हिस्सा बनकर में बहुत ही गौरान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेंने देखा कि ट्रेन संचालन से जुड़े हुए सभी रेल कर्मचारी पूरी सतर्कता व समर्पण के साथ कार्यरत थे। भारतीय रेलवे देश भर के विभिन्न राज्यों में मिशन मोड में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) पहुंचाकर राहत पहुंचाने का क्रम जारी रखे हुए है। इसी क्रम में पश्चिम रेलवे द्वारा हापा व मुंद्रा पोर्ट से अभी तक महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व दिल्ली में ऑक्सिजन टैंकरों के जरिये कुल १८ ट्रेनों में करीब १७७१.०७ टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) की सुपुर्दगी की जा चुकी है।

सार-समाचार

भाजपा नेता के भतीजे की शादी में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी

आणंद,जिले के चमारा गांव में एक शादी समारोह में शामिल लोग डीजे की ताल पर ऐसे थिरक रहे हैं, जैसे उन्हें कोरोना का कोई खौफ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर किसी के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। दरअसल आणंद जिले की आंकलाव तहसील के चमारा गांव के सरपंच और भाजपा के नेता राजु पढियार के भतीजे की शादी थी। भाजपा नेता के भतीजे की शादी में बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ शामिल हुए बल्कि कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाईं। डीजे के ताल पर बिना मास्क लगाए लोग कोरोना से बेखौफ होकर नाचते नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ है। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि शादी समारोह में शामिल किसी भी व्यक्ति को कोरोना का डर नहीं है और शायद इसीलिए किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है?

मुख्यमंत्री के गृह नगर राजकोट के व्यापारियों ने किया मिनी लॉकडाउन का विरोध

राजकोट,मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के गृह नगर राजकोट के व्यापारियों ने मिनी लॉकडाउन का विरोध करते हुए संपूर्ण लॉकडाउन करने या बाजार खोलने की अनुमति देने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले एक साल से कोरोना संकट की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है और ऐसे में मिनी लॉकडाउन उनका आर्थिक संकट बढा रहा है। बता दें कि राज्य के ८ महानगर समेत ३६ शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू के अलावा अन्य कई पाबंदियां लगाई गई हैं। कई शहरों में सरकार के इस फैसले का समर्थन तो कहीं विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के गृहनगर राजकोट के व्यापारियों ने मिनी लॉकडाउन का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बाजार खोलने की अनुमति देने की मांग की है। व्यापारियों की मांग है या तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाओ या दुकानें खोलने की मंजूरी दो। मिनी लॉकडाउन में ६० प्रतिशत बाजार खुले हैं और ४० प्रतिशत बाजार बंद हैं। ४० प्रतिशत बाजार बंद होने से व्यापारियों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। मिनी लॉकडाउन के कारण व्यवसाय बंद होने से बैंक की किश्तें, कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के लिए मुश्किलें हो रही हैं। बता दें कि मिनी लॉकडाउन

क्रांति समय
Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में आरोपी सरबजीत मोखा गिरफ्तार, पुलिस ने करवाई कोरोना जाँच

जबलपुर। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के अंतरराज्यीय घोटाले में फंसा जबलपुर के सिटी अस्पताल का संचालक सरबजीत मोखा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। घोटाले में नाम आते ही माइनर अटैक का बहाना कर खुद के अस्पताल में भर्ती मोखा, एफआईआर दर्ज होते ही फरार हो गया था। मोखा सोमवार शाम को अचानक प्रकट हुआ और इस बार खुद को कोविड संक्रमित बताकर खुद के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हो गया। रात भर पहरा दे रही पुलिस ने उसकी रैपिड रिपोर्ट निगेटिव आते ही मंगलवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया और ओमती थाने ले आई, जहां मोखा से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार सरबजीत के झूठ को बेनकाब करने के लिए पुलिस ने पहले उसकी कोरोना जांच करवाई जिसमें रैपिड टेस्ट में उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं आरटीपीसीआर जांच के लिए भी सेम्पल लिया गया है। दोनों जांच पुलिस लाइन अस्पताल के चिकित्सकों ने की हैं। माइनर अटैक सहित मोखा के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल की एक टीम गठित की गई है। इससे पहले मंगलवार को ओमती पुलिस उसे थाने ले आई। जहां एसआईटी उससे पूछताछ कर रही है।

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता को बदमाशों ने मारी गोली

चिनसुराह (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में मंगलवार को अज्ञात उपद्रवियों ने तृणमूल कांग्रेस के एक नेता को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना उस वक्त हुई जब वह एक स्थानीय बाजार में सब्जी खरीद रहे थे। उन्होंने कहा कि बंसबेरिया नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य नियोगी को गंभीर हालत में पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें कोलकाता रैफर कर दिया गया। भाजपा सूत्रों ने दावा किया कि यह घटना सत्ताधारी दल के अंदर गुटबाजी का नतीजा है। आरोपों से इनकार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री तपन दासगुप्ता ने कहा, फ्रभगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कुछ गद्दारों ने साथ दिया, जिनका हाल में हुए चुनावों के दौरान पर्दाफाश हुआ था।फ्र इस घटना के विरोध में बंसबेरिया इलाके में कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अधिकारी ने कहा कि घटनास्थल पर पुलिस को तैनात कर आगे की जांच की जा रही है और बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

तेलंगाना ने 12 मई से 10 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की, 4,826 नए मामले

हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को राज्य में 12 मई से 10 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने 12 मई (बुधवार) सुबह 10 बजे से अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। विज्ञप्ति के अनुसार, ''हालांकि सुबह छह बजे से सुबह 10 बजे तक सभी दैनिक गतिविधियों में छूट रहेगी।'' सोमवार को तेलंगाना में कोविड–19 के 4,826 नए मामले सामने आए जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 50 हजार से अधिक हो गई, वहीं संक्रमण से 35 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 2,771 हो गयी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने कोविड–19 रोधी टीकों कीखरीद के लिए वैश्विक निविदा जारी करने का फैसला किया है।

जम्मू–कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया

श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जिले में कोमेरनाग के वाइलू में आतंवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जिसके बाद बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि अभियान में तीन आतंकवादी मारे गए। ताजा रिपोर्ट मिलने तक अभियान जारी था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र को लेकर केन्द्र और दिल्ली सरकार को दिए निर्देश

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्र और दिल्ली सरकार को उस जनहित याचिका को एक प्रतिवेदन के रूप में लेने का निर्देश दिया, जिसमें स्टेडियम सहित खुले इलाकों में 'ड्राइव–इन' टीकाकरण केन्द्रों को स्थापित करने की मांग की गई है। 'ड्राइव–इन' टीकाकरण केन्द्रों से तात्पर्य उन केन्द्रों से है जहां आप अपने वाहन से उतरे बिना टीका लगवा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने केन्द्र और दिल्ली सरकार को कहा कि मामले के तथ्यों के लिए लागू कानून, नियमों, विनियमों और नीति के तहत प्रतिवेदन पर फैसला लें। अदालत ने कहा कि फैसला जल्द से जल्द और व्यवहारिक रूप से लिया जाए। दिल्ली के एक व्यापारी अमनदीप अग्रवाल की ओर से दायर उक्त याचिका में मुंबई की तरह 'ड्राइव–इन' टीकाकरण केन्द्रों को स्थापित किए जाने की मांग की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वरिष्ठ नागरिक किसी के सम्पर्क में ना आएं और टीकाकरण के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का भी पालन हो।

राजनाथ सिंह का बयान, कहा–कोरोना से निपटने के लिए काम जारी, अलोचना करने की बजाय कमी लगे तो सुझाव दें

लखनऊ। (एजेंसी)।

कोरोना वायरस से निपटने के मामले में विपक्ष की लगातार आलोचनाओं का जवाब देते हुये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को यहां कहा कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस चुनौती से निपटने के लिये जितना हो सकता है कर रही हैं और यदि कोई चूक रह जाती है तो आलोचना करने के बजाय सुझाव दिये जाने चाहिए। रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद सिंह मंगलवार को राजधानी के कानपुर रोड स्थित हज हाऊस में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा बनाये गये 255 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल की शुरूआत करने आये थे। इससे पहले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने पांच मई को राजधानी के अवध शिल्पग्राम में 450 से अधिक बिस्तर वाले अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल की शुरूआत की थी।

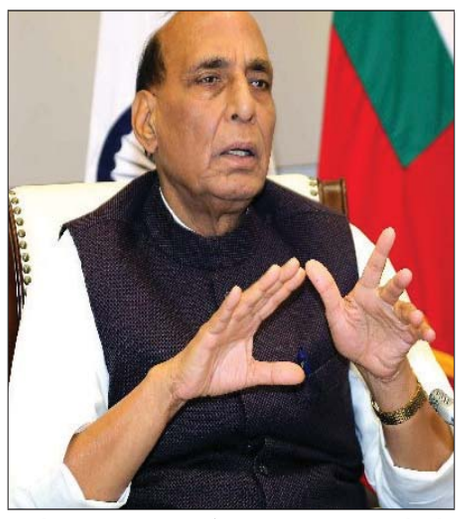

बाद में रक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के मामलों से निपटने में जितनी तत्परता दिखाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाये, कम है। खामियां किसी से भी हो सकती हैं, जो काम करेगा उसी से कहीं कोई चूक भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि

आलोचना का समय नहीं है। यदि कहीं पर किसी को कोई कमी दिखाई देती है और यदि वह अपना सुझाव देता है तो प्रदेश सरकार स्वागत करेगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और इस चुनौती से निपटने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, सरकार कर रही है।'' सिंह ने कहा, ''प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध बनाने में कामयाबी हासिल की है, उसी का परिणाम है कि देश में इस संकट के समय विश्व के कई देश मदद के लिये तैयार हैं और मदद मुहैया भी करा रहे हैं।

सिंह ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जो जानें गयी हैं, उनके परिवारों के प्रति भी मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी की है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को ट्वीट में कहा, भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्?य उ?तर प्रदेश में राज्?य सरकार ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के मामलों का पता घर-घर जाकर लगा रही है और त्?वरित पृथक-वास, रोग प्रबंधन और संपर्कों का पता कर इसका प्रसार रोक रही है। सिंह ने कहा कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस चुनौती से निपटने के लिये हरसंभव प्रयास कर रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री सिंह का आभार व्यक्त किया।

भाजपा सांसद वरुण गांधी 100 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पीलीभीत पहुंचे

पीलीभीत (उ़प्र)। (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी मंगलवार को अपने निजी धन से 100 ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप लेकर यहां पहुंचे और यह खेप जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हवाले की। वरुण गांधी ने इस अवसर पर अपने बयान में कहा कि कोरोना संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए वह अपनी संपत्ति भी गिरवी रखने को तैयार हैं। गांधी ने कहा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने पीलीभीत के लोगों से वादा किया था कि वह उनकी मदद के लिए 100 बड़े सिलेंडर भेजेंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। ऑक्सीजन सिलेंडरों की इस खेप को सांसद ने अपने ही प्रयासों से मुंबई से मंगवाया है। उन्होंने कहा कि पीलीभीत जिला मेरा परिवार है और यहां पर कोरोना संकट से निपटने में हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, इस संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए अपनी संपत्ति भी गिरवी रखने को तैयार हैं।

योगी के नेतृत्व में यूपी में एग्रेसिव टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति पर हो रहा काम, मिल रहे अच्छे परिणाम

लखनऊ। (एजेंसी)।

अपर मुख्य सचिव 'सूचना' नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में एग्रेसिव टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति पर कार्य करने से कोविड संक्रमण के नियंत्रण में अच्छे परिणाम मिल रहे है। उन्होंने बताया कि 01 मई, 2021 को प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 3,01,833 थी, जो लगभग 77,000 घटकर आज 2,25,271 हो गयी है। इसी तरह प्रदेश में नये मामलों की संख्या 01 मई, 2021 के 30,317 से घटकर आज 21,331 हो गयी है। प्रदेश में 01 मई को 2 लाख 79 हजार लोग होमआइसोलेशन में थे जिनकी संख्या घटकर 1 लाख 66 हजार हो गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के प्रतिदिन 2 लाख से अधिक टेस्ट किये जा रहे है। सहगल ने बताया कि सर्विलान्स के माध्यम से घर घर जा कर लोगों से कोविड के लक्षणों की जानकारी ली जा रही है। सर्विलान्स के माध्यम से प्रदेश में अब तक 16.66 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच कर उनका हाल-चाल जाना गया है। उन्होंने बताया कि सर्विलान्स के साथ-साथ 97 हजार राजस्व गाँवों में लोगों से सम्पर्क करते हुए कोविड लक्षणयुक्त लोगों की पहचान कर उनका कोविड टेस्ट तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान की जा रही है। गाँव में निगरानी समिति के द्वारा गाँव में रहने वाले लोगों से सम्पर्क कर कोविड लक्षणों की जानकारी ली जा रही है। कोविड लक्षण मिलने वाले लोगों की आरआरटी टीम द्वारा एन्टीजन कोविड टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गाँव में संक्रमणयुक्त लोगों को होमआइसोलेशन में रखने के लिए गाँव में ही पंचायत भवन/स्कूल/सरकारी इमारतों में आइसोलेट करके उनका उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु के लोगों के साथ-साथ 45 वर्ष से अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिसके तहत अब तक 1 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। 18 से 44 वर्ष के आयु के लोगों के वैक्सीनेशन 7 जनपदों से बढ़ाकर अब 18 जनपदों में किया जा रहा है।

सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा कल वाराणसी में कोविड-19 के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी एवं डीआरडीओ द्वारा निर्मित कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिये गये है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री जी द्वारा गोरखपुर में एम्स तथा बीआरडी मेडिकल कॉलेज की समीक्षा एवं निरीक्षण किया गया है। आज ही मुख्यमंत्री जी अयोध्या में कोविड-19 की समीक्षा कर रहे है तथा मौके पर जाकर निरीक्षण करेगें। सहगल ने बताया कि प्रदेशव्यापी आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आंशिक कोरोना कर्फ्यू में वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल सम्बन्धी कार्य आदि आवश्यक अनिवार्य सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। आंशिक कोरोना कर्फ्यू की अवधि में पूरे प्रदेश के शहरों और गांवों में विशेष सफाई एवं फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोविड बेडों की संख्या निरन्तर बढ़ायी जा रही है। इसी क्रम में नॉन आक्सीजन बेड को आक्सीजनयुक्त बेड में बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में आक्सीजन प्लांट लगाये जा रहे है। साथ ही 21,000 आक्सीजन कन्सटेंटर खरीदे जा रहे है। कल अस्पतालों में 1003 मीट्रिक टन आक्सीजन की सप्लाई की गयी है। उन्होंने बताया कि होमआइसोलेशन के मरीजों को आक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक जनपद में एक रीफिलर नामित किया जायेगा। सहगल ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां तेजी से चलायी जा रही हैं। लगभग 08 लाख से अधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों द्वारा मजदूरों को काम दिया जा रहा है। इन औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क बनाये गये हैं। इसके अलावा जिन औद्योगिक संस्थानों में 50 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे ऐसे औद्योगिक संस्थानों में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। जिससे वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को समय से इलाज मिल सके।

एनडीआरएफ बनी देवदूत, वाराणसी में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है और इससे मरीजों के मध्य ऑक्सीजन की सतत आपूर्ति की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस संकट की घड़ी में मित्र देश भारत को सहयोग करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट व अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। एनडीआरएफ विदेशों से आयातित ऑक्सीजन प्लांट को विभिन्न राज्यों के चयनित अस्पतालों तक सड़क मार्ग से सुरक्षित पहुंचा कर इनके इंस्टॉलेशन में अपनी अग्रिम भूमिका निभा रही है। जिससे मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता निर्बाध रूप से मिलती रहे। ये ऑक्सीजन प्लांट अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, इटली व आयरलैंड से आयातित किए गए हैं जिसे देश भर के विभिन्न अस्पतालों में लगाए जा रहे है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इजराइल से आयातित 500 लीटर प्रति मिनट की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट को लाने का दायित्व 11 एनडीआरएफ की टीम को सौंपा है, जिसे सड़क मार्ग से सुरक्षित लाकर ईएसआईसी अस्पताल पांडेपुर में प्रशासन व अस्पताल प्रबन्धन के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस इस अवसर पर एनडीआरएफ वाराणसी के कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि एनडीआरएफ उत्तर प्रदेश के आपदा प्रबंधन में सदैव उत्कृष्ट व अग्रणीय भूमिका निभाती रही है। पिछले वर्ष से जारी करोना संकट के प्रबंधन में राज्य के विभिन्न स्थानों में रासायनिक छिड़काव द्वारा सेनिटाइजेशन, कोविड संक्रमण के प्रति जागरूकता तथा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में प्रशासन के सहयोग से भोजन वितरण भी किया गया है और आज की आपातकालीन स्थिति में कोरोना महामारी से निपटने के लिए एनडीआरएफ संकल्पबद्ध है। ईएसआईसी हॉस्पिटल में यह आक्सीजन प्लांट लगने से कोविड रोगियों को आक्सीजन सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सकेगा।

राज्यों को आगामी तीन दिन में मिलेंगी कोविड–19 टीके की सात लाख और खुराक : केंद्र सरकार

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी कोविड-19 टीके की 90 लाख से अधिक खुराक हैं और सात लाख से अधिक खुराक आगामी तीन दिन में उन्हें वितरित की जाएंगी। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 18 करोड़ से अधिक (18,00,03,160) खुराक निःशुल्क दी हैं, जिनमें से 17,09,71,429 करोड़ खुराकों की खपत हो चुकी है। उसने कहा, ''राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास 90 लाख से अधिक खुराक (90,31,691) अब भी हैं।'' उसने कहा कि जिन राज्यों ने कम आपूर्ति दिखाई है, वे टीकों की आपूर्ति की तुलना में अधिक खपत दिखा रहे हैं, जिनमें बर्बाद हुई खुराक भी शामिल हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने ''सशस्त्र बलों को मुहैया कराए गए टीकों को शामिल नहीं किया है''। मंत्रालय ने बताया

कि आगामी तीन दिन में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को 7,29,610 और खुराक दी जाएंगी। उसने बताया कि भारत सरकार राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 टीका निःशुल्क मुहैया कराके राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम में मदद कर रही है। कोविड- 19 टीकाकरण की 'उदारीकृत और त्वरित चरण तीन रणनीति' एक मई, 2021 से शुरू हो गई है। रणनीति में यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा स्वीकृत टीकों की खुराक का 50 प्रतिशत ही खरीदेगी और इन्हें राज्य सरकारों को पहले की तरह निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया, संशोधित केन्द्रीय एमटीपी कानून अभी तक लागू नहीं किया गया है

मुंबई।(एजेंसी)।

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि केन्द्र के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) कानून (वैधानिक तरीके से गर्भपात संबंधी कानून) में हाल में हुए संशोधन को कोविड-19 महामारी के कारण अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। इन संशोधनों में 22 सप्ताह (साढ़े पांच महीने) की गर्भावस्था तक कानूनी रूप से गर्भपात कराने की बात है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 मार्च, 2021 को एमटीपी (संशोधन) विधेयक पर हस्ताक्षर किये थे और केन्द्र सरकार ने उसे अधिसूचित किया है। सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने न्यायमूर्ति के. के. तातेड़ और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ को बताया, ''लेकिन, कोविड-19 महामारी के कारण इसे लागू करने में देरी हो रही है।'' पीठ कानूनी रूप से गर्भपात कराने संबंधी तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से दो याचिकाकर्ताओं को 22 सप्ताह की गर्भावस्था है और उन्होंने बच्चे में स्वास्थ्य संबंधी विकारों के कारण उसके जीवित रहने की क्षीण संभावनाओं को

देखते हुए गर्भपात का अनुरोध किया है। वहीं तीसरा मामला एक बलात्कार पीड़िता का है जिसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। मार्च, 2021 में हुए संशोधन से पहले कम से कम दो चिकित्सक के अनुमति देने पर 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था में गर्भपात कराया जा सकता था, अब इस अवधि को बढ़ा कर 22 सप्ताह कर दिया गया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहली दो याचिकाकर्ताओं को गर्भपात कराने के लिए अदालत से अनुमति लेने की जरुरत नहीं है। ऐसे में सरकार के वकील ने कानून के लागू होने में हुई देरी की सूचना दी।

पति की सांसों के बदले पत्नी के साथ अस्पताल कर्मचारी ने किया यौन उत्पीड़न, पानी के लिए भी तरसाया

नई दिल्ली।(एजेंसी)।

भारत में कोरोनावायरस की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। कोरोना से हुई मौतों के कारण शमशानों में शवों की लाइन लगी है। कुछ लोग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं तो कुछ घरों पर उपचार कर रहे हैं। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति ने मानसिक रुप से काफी परेशान किया है। इस लहर के दौरान हर किसी ने अपने करीबियों को खोया है। यह स्थिति भयानक है। कोविड -19 से शारीरिक, वित्तीय स्थिति के साथ-साथ लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे दुख की घड़ी में कुछ लोग फरिश्ता बनकर भी सामने आये और लोगों की मदद की।अविश्वास और सद्भावना की कई कहानियाँ हैं, जिन्होंने आशा को जीवित रखा है। इस अच्छाई के साथ-साथ कुछ ऐसे भी लोगों के चेहरे सामने आये जिन्होंने महामारी में लोगों का फायदा उठाया ऑक्सीजन , दवाइयों की काला बाजारी की। यहां तक भी इंसान की नियत समझ आती है लेकिन बिहार के एक अस्पताल से कथित तौर पर जो घटना सामने आयी है उसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार करके रख दिया है।

यह घटना बिहार के भागलपुर से है जहा एक महिला ने कथित तौर पर अपने कोरोना वायरस से पीड़ित पति को जिंदा रखने के लिए में लगभग एक महीने तक संघर्ष किया। उनके पति की इसी महीने पटना के एक निजी अस्पताल में कोरोना से जंग के बाद मौत हो गयी। महिला ने अपने पति की मौत के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को जिम्मेदार माना है। महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उसने अस्पताल के लोगों पर काफी गंभीर आरोल लगाये हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि जब वह अपने कोविड-पॉजिटिव पति के इलाज के लिए प्रयास कर रही थी, तो बिहार के एक अस्पताल में कर्मचारियों द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। महिला ने अपने पति की मौत के लिए चिकित्सकीय लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया है। उसने अस्पताल पर ब्लैक में ऑक्सीजन बेचने का भी आरोप लगाया। वीडियो में महिला ने कहा कि वह और उसका पति होली मनाने के लिए मार्च में नोएडा से बिहार आए थे। बिहार आने के बाद महिला के पति की तबियत ठीक नहीं थी। वो 11 अप्रैल को बीमार हो गया। महिला ने बताया कि उसके पति ने कोरोनोवायरस का दो बार परीक्षण करवाया लेकिन दोनों बार रिपोर्ट नेगिटिव आयी। महिला के पति ने आखिर में अपनी टेस्ट का एक्सरे करवाया जिसमें फेफड़ों का संक्रमण दिखाई दिया। एक दिन बाद उस व्यक्ति और उसकी माँ को भागलपुर के ग्लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए, महिला ने कहा कि अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी गायब थे जो मौजूद थे उन्होंने दवा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति, जो संघर्ष कर रहे थे, पानी के लिए संकेत दे रहे थे लेकिन किसी ने भी उन्हें पानी नहीं दिया। महिला ने कहा कि उसने एक परिचारक से अस्पताल में रहने में मदद करने का अनुरोध किया। उसने कहा कि वह अपने पति से बात कर रही थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके दुपट्टे को खींच रहा है। मैं अपने पति से बात करते हुए पीछे मुड़ी तो वह मेरी कमर पर हाथ रख कर मुस्कराने लगा। मेरी मां ने भी उसे ऐसा करते हुए देखा। मैंने दुपट्टे को छीन लिया, लेकिन कुछ भी नहीं कह सका क्योंकि मुझे डर था। उसने कहा कि वह डरती थी कि अगर उसने आवाज उठायी तो वह उसकी माँ या उसके पति के लिए कुछ नहीं करेगा।

महिला ने कहा कि उसके पति की हालत खराब हो गई है, जिसके बाद उसे मायागंज में इलाज के लिए भेजा गया। उसने आरोप लगाया कि भागलपुर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने उसके पति को भर्ती होने से मना कर दिया या उसके रोने के बावजूद उसे ऑक्सीजन देने से मना कर दिया। उसने यह भी आरोप लगाया कि मायागंज में डॉक्टर और कर्मचारी अपने कमरों में रोशनी बंद कर देंगे और लोगों के मरने पर भी अपने मोबाइल फोन पर फिल्में देखेंगे। मायागंज से महिला के पति को पटना के राजेश्वर अस्पताल ले जाया गया। उसने कहा कि उसने एक एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसे दिल्ली लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने की वजह से नहीं ला सकी। महिला ने कहा कि स्थिति यहां अलग नहीं थी। उसने अस्पताल के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने उसके पति की ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती कर दी, जिसके कारण उसे काला बाजार से सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। अस्पताल ने ऑक्सीजन सिलेंडर को 50,000 रुपये में बेचा। लोगों से अपने प्रियजनों की देखभाल करने और अस्पतालों पर भरोसा न करने की अपील करते हुए, महिला ने कहा कि उसने अपने पति को कोरोनावायरस से नहीं खोया, लेकिन चिकित्सा लापरवाही और ऑक्सीजन के कारण खोया है। कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान, बिहार उन राज्यों में से एक है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बिहार में सोमवार को 75 कोविड -19 हताहतों की संख्या बढ़कर 3357 हो गई, जबकि कुल पुष्टि मामलों में छह लाख का आंकड़ा पार कर गया।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)